वर्ष 12 • अंक 17 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 7 मार्च 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

मासिक कोटा बढ़ने से चीनी में गिरावट

वेंकटेश गोपालकृष्णन पृष्ठ 2

अबु धाबी इन्वेस्टमेंट संग शापूरजी पलोनजी का करार

डॉलर रु. 70.30 ▼ 20 पैसे | यूरो रु. 79.50 ▼ 40 पैसे | सोना (10ग्राम) रु. 32095 ▼ 40 रुपये | सेंसेक्स 36636.10 ▲ 193.60 | निफ्टी 11053.00 ▲ 65.50 | निफ्टी फ्यूचर्स 11086.80 ▲ 33.80 | ब्रेंट क्रूड 64.90 डॉलर ▲ 0.10 डॉलर

एक नज़र

फेसबुक के कथित दुरुपयोग पर पूछे सवाल

संसद की एक समिति ने चुनावों के दौरान सोशल मीडिया मंच का दुरुपयोग रोकने की अमेरिकी कंपनी फेसबुक की कथित अक्षमता पर चिंता जाहिर की है। फेसबुक के उपाध्यक्ष (ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी) जोएल कपलान बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष हाजिर हुए। सूत्रों ने बताया कि फेसबुक ने यह आश्वासन दिया है कि वह चुनाव के समय अपने मंच पर विज्ञापन देने वालों की पहचान, उनका स्थान और उसका भुगतान करने वालों की पहचान एक अलग पन्ने पर उपलब्ध कराएगी।

डीएचएफएल का शेयर 11 प्रतिशत उछला

दीवान हाउसिंग फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) का शेयर बुधवार को 11 प्रतिशत उछल गया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी ने यह पुष्टि की है कि डीएचएफएल ने रकम की हेराफेरी के लिए मुखौटा कंपनियों का सहारा नहीं लिया था। कंपनी के शेयर में इस रिपोर्ट के बाद तेजी आई। शेयर बीएसई पर 11.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 148.80 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 20 प्रतिशत तक ऊपर चला गया था। एनएसई में कंपनी का शेयर 11 प्रतिशत तेजी के साथ 148.75 रुपये पर बंद हुआ। पृष्ठ 2

'मंत्रालय से चुराए गए राफेल के दस्तावेज'

केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि रक्षा मंत्रालय से राफेल विमान सौदे से जुड़े दस्तावेज मौजूदा या पूर्व कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं। केंद्र ने कहा कि समाचार-पत्रों ने इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में कथित गड़बड़ियों से जुड़ी खबरें प्रकाशित की हैं। महान्यायवादी के के वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि ये दस्तावेज रक्षा सौदों से संबंधित हैं और शासकीय गोपनीयता अधिनियम के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उन समाचार पत्रों के खिलाफ 'आपराधिक कार्रवाई' के बारे में विचार कर रही है, जिन्होंने ये खबरें प्रकाशित की हैं। सरकार उन याचियों पर भी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने दस्तावेज का अपनी याचिका में इस्तेमाल किया है। पृष्ठ 14

आज का सवाल

क्या नए मानक पर बैंकों को मिलेगी आरबीआई से मोहलत

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या अमेरिका के जीएसपी दर्जा वापस लेने से निर्यात होगा प्रभावित?	हां	60.00%
	नहीं	40.00%

नए लेखा मानक, बैंक चाहें मोहलत

कर्ज नुकसान के लिए ज्यादा प्रावधान और लंबित विधायी संशोधनों का दिया हवाला

अभिजित लेले
मुंबई, 6 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देश के मुताबिक बैंकों में भारतीय लेखा मानक 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होने जा रहे हैं, लेकिन बैंक इन्हें लागू करने की तिथि आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फंसे कर्ज के लिए ज्यादा पूंजी का प्रावधान करने के अलावा लंबित विधायी संशोधनों तथा बैंकिंग नियामक द्वारा अंतिम नियमों को जारी करने में देरी का हवाला देते हुए बैंक इन्हें टालने की मांग कर रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के प्रबंध निदेशक ने कहा, 'सरकार ने बैंकों को कठिन समय में पूंजी दी है और बैंकों पर अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने का दबाव है। भारतीय लेखा मानक लागू करने से बैंकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, खास तौर पर कर्ज नुकसान के प्रावधान के मामले में।' इसलिए बैंक आरबीआई से कुछ मोहलत मांग रहे हैं। बैंकर ने कहा, 'स्थिति में सुधार होने के बाद ही हम नए लेखा मानक अपनाने में सक्षम हो सकेंगे।'

अगर आरबीआई इसे टालता है तो यह दूसरा मौका होगा जब भारतीय लेखा मानक लागू करने की तिथि बढ़ाई जाएगी। 2016 की आरबीआई की मूल योजना के मुताबिक बैंकों को अप्रैल 2018 से भारतीय लेखा मानक को लागू करना था। लेकिन आरबीआई ने इसे एक साल आगे बढ़ाकर अप्रैल 2019 कर दिया क्योंकि इसके लिए जरूरी विधायी संशोधन लंबित था।

भारतीय लेखा मानक टालने की मांग क्यों?

- फंसे कर्ज के लिए ज्यादा प्रावधान का डर
- अब तक विधायी संशोधन नहीं हुआ है
- आरबीआई की ओर से दिशानिर्देश नहीं हुए हैं जारी
- सॉफ्टवेयर में करना होगा बदलाव

नए लेखा मानक के लाभ

- देनदारियों के बारे में वास्तविक हालात का चलेगा पता
- बैंकिंग प्रणाली में बढ़ेगी पारदर्शिता
- वैश्विक लेखा मानकों के अनुरूप

मुंबई मुख्यालय वाले एक सार्वजनिक बैंक के शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'मौजूदा हालात में नए लेखा नियम अप्रैल से प्रभावित हो जाएंगे। वर्तमान पूंजी की जरूरतों को नए लेखा मानकों में ध्यान नहीं रखा गया है। अगर नए लेखा नियमों को लागू किया जाता है पूंजी की जरूरत बढ़ जाएगी।'

नए लेखा नियमों में कर्ज नुकसान के लिए प्रावधान को अनुमानित उधारी नुकसान मॉडल के तहत करने की बात कही गई है जबकि बैंक इसके लिए ऐतिहासिक कर्ज नुकसान अनुभव के आधार पर प्रावधान करते हैं और इसमें भविष्य के आर्थिक हालात तथा अनुमानों को भी ध्यान में रखा जाता है।

एक बैंकर ने कहा कि आरबीआई ने अभी नए लेखा नियमों को लेकर निर्दिष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किया है और वित्त वर्ष खत्म होने में कुछ हफ्ते ही बचे हैं। बैंकों को आकलन प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर प्रणाली में बदलाव का मूल्यांकन करने की जरूरत होगी और डेटा संग्रह प्रणाली सुदृढ़ बनानी होगी। एक वरिष्ठ बैंकर ने कहा, 'सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना होगा। ऐसे में इसके अप्रैल से लागू करने में कठिनाई हो सकती है।'

(शेष पृष्ठ 3 पर)

दीवाली पर रिलायंस के ई-कॉमर्स की दस्तक

युवराज मलिक
बेंगलूरु, 6 मार्च

इस साल त्योहारी मौसम में ऑनलाइन खरीदारी पर ग्राहकों को ज्यादा छूट मिल सकती है क्योंकि मुकेश मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज इस साल दीवाली पर अपने ई-कॉमर्स कारोबार की धमाकेदार दस्तक की तैयारी कर रही है।

मामले से जुड़े दो सूत्रों ने कहा कि आरआईएल दीवाली पर ई-कॉमर्स कारोबार शुरू करने की तैयारी कर रही है। विश्लेषकों का कहना है कि अभी तक फ्लिपकार्ट (अब वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी) बिग बिलियन डे और एमेजॉन इंडिया अपने ग्रेट इंडियन दीवाली सेल के जरिये एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती रही है। ऐसे में अंबानी के इस क्षेत्र में आने से प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो जाएगी। कंसल्टेंसी फर्म रेडसीर के अनुसार अक्टूबर-नवंबर 2018 के दौरान ई-कॉमर्स फर्मों ने 4.3 अरब डॉलर के सामान की बिक्री की थी।

सूत्रों ने कहा कि आरआईएल ई-कॉमर्स कारोबार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है, जिसे कंपनी के अंदर नया कॉमर्स नाम दिया गया है। इसके तहत कंपनी अक्टूबर-नवंबर में देश भर में ई-कॉमर्स सेवा शुरू कर सकती है। इसके लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलूरु सहित छह शहरों में परीक्षण भी किया जा रहा है।

नवी मुंबई के रिलायंस कॉरपोरेट पार्क में एक समर्पित टीम अंबानी के करीबी मनोज मोदी के नेतृत्व में इसका पूरा कामकाज देख रही है। रिलायंस की योजना अपने रिटेल नेटवर्क - रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश और रिलायंस ट्रेंड्स के साथ ही असंगठित क्षेत्र के हजारों स्टोरों को इसके साथ जोड़ने की है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

छह शहरों में रिलायंस कर रही है अपने ई-कॉमर्स का परीक्षण

एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों को मिलेगी कड़ी टक्कर

चुनाव प्रचार पर भाजपा-कांग्रेस ने खोली तिजोरी

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 6 मार्च

देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा अगले सप्ताह से आम चुनावों के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू कर सकते हैं। विज्ञापन उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से इसकी पुष्टि की है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 8 या 9 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है जिसके साथ देश में आदर्श आचारसंहिता लागू हो जाएगी। इसके लागू होते ही सरकारी विज्ञापन बंद जाएंगे जो अभी मीडिया में छाए हुए हैं। इनके जरिये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार अपनी योजनाओं, नीतियों और आगे के कार्यक्रमों का प्रचार कर रही है। आचार संहिता के लागू होने के बाद भाजपा और कांग्रेस का प्रचार अभियान जोर पकड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक 2014 के चुनावों की तरह इस बार भी प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा होंगे जबकि कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी पर होगी। प्रचार के पहले दौर में भाजपा ने कम से कम 500-600 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 2014 में पार्टी ने फरवरी-मार्च से अप्रैल-मई तक अपने चुनाव प्रचार में करीब 700 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

इस बार चुनाव प्रचार की अवधि कम होगी लेकिन भाजपा इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी के प्रचार का जिम्मा ओगिल्वी समूह के पास है। वर्ष 2014 में भाजपा ने अपने प्रचार के लिए विज्ञापन एजेंसी सोहो स्क्वायर (अब 82.5 कम्युनिकेशंस) और मैकेन वर्ल्डग्रुप की विज्ञापन कंपनी टीएजी की सेवाएं ली थी। सोहो स्क्वायर ओगिल्वी समूह और का हिस्सा है। सोहो स्क्वायर ने ही 'अबकी बार मोदी सरकार' जैसे नारे गढ़े थे जबकि मैकेन वर्ल्डग्रुप ने भाजपा का चुनावी गीत 'सौगंध मिट्टी की' जारी किया था।

दूसरी ओर कांग्रेस आम चुनावों के लिए अभी तक प्रचार एजेंसियों को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। इसमें एफसीबी इंडिया और लिओ बर्नेट होड़ में हैं। (शेष पृष्ठ 4 पर)

सेवानिवृत्ति की उम्र तक नहीं हटेंगे अतिथि शिक्षक

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 6 मार्च

दिल्ली सरकार के निर्णय से अतिथि शिक्षकों को आज बड़ी राहत मिली। दिल्ली मंत्रिमंडल ने उस नीति मंजूरी दे दी, जिसमें अतिथि व अनुबंध वाले शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र यानी 60 वर्ष तक नहीं हटाने का प्रावधान है। सरकार की इस नीति से करीब 22 हजार अतिथि शिक्षकों को फायदा होगा। सरकार ने इस नीति को उप राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। इन शिक्षकों का अनुबंध 28 फरवरी को समाप्त हो गया था, जिसके बाद से अतिथि शिक्षक विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे।

मंत्रिमंडल बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस समय कुछ कक्षाओं की परीक्षाएं चल रही हैं और अगले महीने से नया सत्र शुरू होना है। ऐसे में 22 हजार अतिथि शिक्षकों को हटाने से पठन-पाठन पर असर पड़ेगा। कुल कार्यरत शिक्षकों में अतिथि व अनुबंध पर रखे गए शिक्षकों की हिस्सा 38 फीसदी है। सिसोदिया ने कहा कि शिक्षकों के हटाए जाने से जो स्थिति आज पैदा हुई, यह आगे न हो।

इसे सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने एक नीति को मंजूरी दी है। जिसके मुताबिक अब अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र तक काम करते रहेंगे। दिल्ली में नियमित शिक्षकों के सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है। अतिथि शिक्षकों को भी 60 साल की उम्र से पहले नहीं हटाया जाएगा।

सिसोदिया ने बताया ' चूंकि सेवा मामले उप राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए इस नीति को मंजूरी के लिए उप राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है।'

सिसोदिया ने कहा कि हरियाणा ने भी अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की उम्र तक न हटाने की नीति लागू की है। ऐसे में उप राज्यपाल को दिल्ली सरकार की इस नीति को मंजूरी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस संबंध में नीति को दी मंजूरी

22 हजार अतिथि शिक्षकों को होगा फायदा

खबरों में रहे स्टॉक

रेप्को होम फाइनैंस

एचडीएफसी एमएफ ने हिस्सेदारी बढ़ाई

₹ 427.75 पिछला बंद भाव
₹ 450.50 आज का बंद भाव
▲ 5.32 %

एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजिज

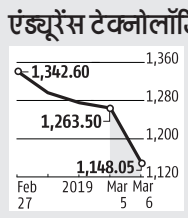

ओएफएस के लिए आधार मूल्य 1,100 रुपये तय

₹ 1,263.50 पिछला बंद भाव
₹ 1,148.05 आज का बंद भाव
▼ 9.14 %

लक्ष्मी विलास बैंक

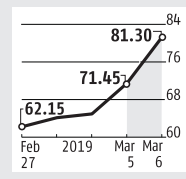

बोर्ड 8 मार्च को रकम जुटाने की योजना पर करेगा विचार

₹ 71.45 पिछला बंद भाव
₹ 81.30 आज का बंद भाव
▲ 13.79 %

दीवान हाउसिंग फाइनैंस कॉरपोरेशन

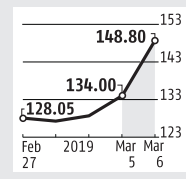

किसी भी मुखौटा कंपनी को प्रोत्साहन नहीं

₹ 134.00 पिछला बंद भाव
₹ 148.80 आज का बंद भाव
▲ 11.04 %

एडलवाइस फाइनैंशियल सर्विसेज

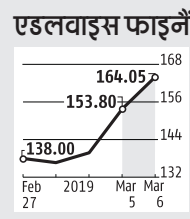

एनबीएफसी इकाई में सीडीपीक्यू करेगी 1,800 करोड़ रुपये का निवेश

₹ 153.80 पिछला बंद भाव
₹ 164.05 आज का बंद भाव
▲ 6.66 %

संक्षेप में

ग्रासिम इंडस्ट्रीज की होगी सोकतास इंडिया

ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने बुधवार को कहा कि वह कपड़ा क्षेत्र की कंपनी सोकतास इंडिया का 165 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करेगी। सोकतास इंडिया की प्रीमियम कपड़ों के बाजार में अच्छी उपस्थिति है। उसके कपड़े सोकता, गिजा हाउस ब्रांड नाम के तहत बिकते हैं। इन कंपनियों के एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज इस अधिग्रहण सौदे का वित्तपोषण पूरी तरह से अपने आंतरिक संसाधनों से ही करेगी। *भाषा*

स्पाइसजेट ने अमेडस को बनाया बिक्री साझेदार

स्पाइसजेट ने यात्रा से जुड़े प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी अमेडस को अपना पहला वैश्विक वितरण साझेदार नियुक्त किया है। अमेडस, स्पाइस जेट को नए बाजारों और दुनियाभर के यात्रियों तक पहुंचने में मदद करेगी। स्पाइसजेट ने बुधवार को एक बयान में बताया कि स्पाइसजेट के सभी टिक्ट घरेलू यात्रियों को मौजूदा नेटवर्क के साथ-साथ अब अमेडस पर भी उपलब्ध होंगे। *भाषा*

स्टरलाइट कारखाने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं जारी

वेदांत लिमिटेड ने कहा है कि तूतीकोरिन कॉपर कारखाना फिर से खोलने के लिए राज्य अदालतों के जरिए कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं। उग्र प्रदर्शन के कारण तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल मई में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को खनन समूह के तांबा संयंत्र को सील करने और स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया था। *भाषा*

एडीआईए संग शापूरजी का करार

1.2 अरब डॉलर के लॉजिस्टिक्स फंड के लिए अबु धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी संग करार

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 6 मार्च

लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रकम जुटाने की योजना में से एक के तहत शापूरजी पलोनजी समूह ने 1.2 अरब डॉलर प्राइवेट इक्विटी फंड जुटाने के लिए अबु धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए) के साथ गठजोड़ किया है, जिसका निवेश देश के लॉजिस्टिक्स सेंटर में किया जाएगा। एक सूत्र ने यह जानकारी दी।

दोनों साझेदार दो चरणों में 60-60 करोड़ डॉलर जुटाएंगे। एक सूत्र ने कहा, शापूरजी समूह 10 करोड़ डॉलर लगाएगा और एडीआईए 50 करोड़ डॉलर। सूत्र ने कहा कि इस फंड के लिए जल्द ही कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और शापूरजी पहले से ही जमीन की तलाश कर रहे हैं।

शापूरजी पलोनजी समूह के प्रवक्ता ने इस मसले पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। अबु धाबी की सॉवरिन फंड एडीआईए से जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब भी नहीं मिला।

शापूरजी पलोनजी रियल एस्टेट के मुख्य कार्याधिकारी वेंकटेश गोपालकृष्णन इस फंड की निगरानी करेंगे, लेकिन सूत्रों ने कहा कि एक अलग सीईओ भी होगा, जिसकी तलाश हो रही है।

सूत्रों ने कहा, शापूरजी निर्माण व रियल एस्टेट के क्षेत्र में है। ऐसे में यह उनके लिए स्वाभाविक क्रियाकलाप है। शापूरजी पलोनजी समूह और एडीआईए के बीच पहले से ही देश में वाणिज्यिक परिसंपत्तियों की खरीद का करार है। शापूरजी पलोनजी रियल एस्टेट ने ऐक्टिस, आईएफसी और एडीबी के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं के लिए साझेदारी की है। जीएसटी ने पूरे देश को एकसमान बाजार बना दिया है, इस वजह से और ई-कॉमर्स से बढ़ती मांग को देखते हुए कई भारतीय व विदेशी कंपनियों ने लॉजिस्टिक्स व वेयरहाउसिंग में निवेश के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है। एक अनुमान के मुताबिक, निवेशकों ने अगले कुछ वर्षों में भारतीय लॉजिस्टिक्स में 4 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

पिछले साल इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट और वेयरहाउसिंग डेवलपर इंडोस्पेस (एवरस्टोन समूह के समर्थन वाली) ने 1.2 अरब डॉलर वाला तीसरा लॉजिस्टिक्स फंड बंद किया है। एक ओर जहां सिंगापुर की मैपलट्री और ब्रिटेन की सीडीसी इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली नई कंपनियां हैं, वहीं दूसरी ओर लोगोस और सिंगापुर की एसेंडस-सिंगब्रिज पहले ही देश में ऐसा उद्यम बना चुकी हैं। कनाडा की सीपीपीआईबी ने इंडोस्पेस के साथ संयुक्त उद्यम करार किया है।

विशेषज्ञों ने कहा कि जीएसटी के फायदे और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की नीति को देखते हुए यह क्षेत्र असंगठित से संगठित क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया है।

एनारॉक कैपिटल के प्रबंध निदेशक शोभित अग्रवाल ने कहा, अगले चार वर्षों में हम कुछ बड़े वेयरहाउस देखेंगे। रकम अच्छे संपत्ति मालिकों, बड़े, पूण4 स्वचालित व स्मार्ट वेयरहाउस का पीछा कर रही है।

इस क्षेत्र में मांग भी बढ़ रही है। लॉजिस्टिक्स व वेयरहाउसिंग क्षेत्र में लिया गया कुल क्षेत्र कैलेंडर वर्ष 2018 के आखिर में 2.4 करोड़ वर्गफुट के पार निकल गया, इस तरह से इसमें 40 फीसदी से ज्यादा की सालाना बढ़ोतरी दर्ज हुई। यह सर्वोच्च आंकड़ा है और यह जानकारी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी सीबीआरई की रिपोर्ट से मिली।

एडीआईए दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट निवेशक मानी जाती है और इसकी परिसंपत्तियां 62 अरब डॉलर के पार चली गई है। इंडोस्यूज वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से प्रकाशित सूची में दुनिया के 10 अग्रणी प्रॉपर्टी निवेशकों में सॉवरिन वेल्थ फंड सबसे आगे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रियल एस्टेट निवेश एडीआईए की कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों का 7.5 फीसदी है।

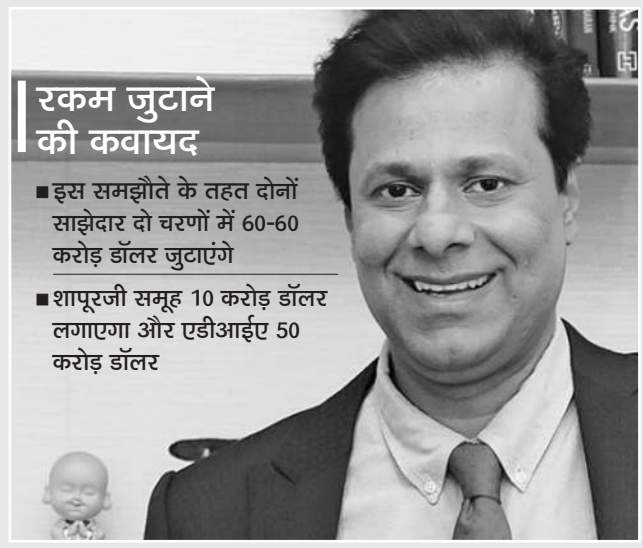

ई-चौपाल के बैंकएंड पर काम कर रही आईटीसी

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 6 मार्च

विविध कारोबार करने वाली कंपनी आईटीसी लिमिटेड अपने ई-चौपाल कार्यक्रम के लिए बैंकएंड को सुदृढ़ करने के लिए एग्रीगेटर मॉडल पर काम कर रही है। फिलहाल ई-चौपाल के तहत देश में 40 लाख किसानों को डिजिटल तौर पर समर्थ बनाया गया है।

उद्योग संगठन सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आईटीसी के प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने कहा, 'डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ काफी संभावनाएं आ रही हैं। हम अपने ई-चौपाल कार्यक्रम के लिए बैकएंड पर काम कर रहे हैं जो ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाएगा ताकि वे किसानों की मदद कर सकें।'

उम्मीद की गई है कि इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण युवाओं को डिजिटल तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा जो आधुनिक प्रौद्योगिकी सीख सकते हैं और मोबाइल फोन ऐप के जरिये हासिल डेटा के साथ किसानों को उपयुक्त जानकारी दे सकते हैं। हालांकि यह कार्यक्रम फिलहाल अपने परीक्षण स्तर में है।

एक मोबाइल फोन ऐप सहित यह एग्रीगेटर मॉडल ई-चौपाल का चौथा संस्करण होगा जो किसानों के लिए ई-सेवा एग्रीगेटर के तौर पर काम करेगा। मौजूदा मॉडल के तहत व्यक्तिगत तौर पर फसल प्रबंधन संबंधी परामर्श सेवाएं दी जाती है। इससे अन्य डिजिटल सेवाएं मुहैया कराने के अलावा ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार में वृद्धि होगी। इसके तहत कहा गया है कि ई-चौपाल के 4.0 मॉडल के तहत डिजिटल प्रौद्योगिकी महज किऑस्क तक सीमित नहीं रहेगी और यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।

चौपाल प्रदर्शन खेत डिजिटल बुनियादी ढांचा का एक पूरक है जो कृषि-विस्तार सेवाओं, खेतों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तालमेल स्थापित करता है। इसके तहत किसानों के लिए बेहतरीन प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाता है और फसल पोर्टफोलियो को विविध बनाने में किसानों की सहायता करता है।

ई-चौपाल मॉडल को साल 2000 में शुरू किया गया था और यह ग्रामीण इंटरनेट किऑस्क का नेटवर्क है। यह औपचारिक बाजार से दूर रहने वाले लघु एवं सीमांत किसानों को सेवाएं मुहैया कराता है और वास्तविक समय आधारित मौसम एवं कीमत संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है।

डीएचएफएल ने नहीं दिया मुखौटा कंपनियों को बढ़ावा

सुब्रत पांडा
मुंबई, 6 मार्च

हाउसिंग फाइनैंस कंपनी डीएचएफएल लिमिटेड की ऑडिट कमेटी की तरफ से रखी गई स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट में मुखौटा कंपनियों की तरफ से रकम की हेराफेरी के सभी आरोपों से फर्म को क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन इसके साथ यह भी कहा गया है कि डीएचएफएल के प्रवर्तकों की तरफ से शुरू की गई कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए कुछ रकम इकाइयों को उधार दी गई हो सकती है।

ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि रियल एस्टेट की चार कंपनियों को झुग्गी पुनर्वास परियोजना के लिए दिए गए कर्ज का इस्तेमाल संभवत: अन्य रियल एस्टेट कंपनी (दर्शन डेवलपर्स) का शेयर खरीदने में किया गया, जो कायटा एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का है। कायटा एडवाइजर्स और इसकी विशिष्ट नाम वाली सहायक कंपनी का प्रवर्तन वधावन ने किया है, जो डीएचएफएल के प्रवर्तक भी हैं और ये रियल एस्टेट और फिल्म प्रोडक्शन समेत विभिन्न कारोबारों में हैं। इन कंपनियों का पता एकसमान है - एचडीआईएल टावर, मुंबई, जो डीएचएफएल लिमिटेड का भी पता है।

डीएचएफएल ने नोशन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ईयरलीन रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राशुल रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, एडवीना रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को एसआरए डेवलपमेंट के लिए परियोजना कर्ज के तौर पर 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए और इसका वितरण भी किया।

फिलिप मॉरिस ने रोक के बावजूद किया भुगतान

फिलिप मॉरिस इंटरनैशनल इंक ने अपने मार्लबोरो सिगरेट बनाने के लिए भारतीय साझेदार को वर्षों से विनिर्माण लागत का भुगतान करती रही है जबकि सरकार ने नौ साल पहले ही इस उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर प्रतिबंध लगा दिया था। रॉयटर्स को प्राप्त कंपनी के आंतरिक दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है।

भारत सरकार ने 2010 में सिगरेट विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी ताकि धूम्रपान पर रोक लगाने के प्रयासों को बल मिल सके। सरकार के इस निर्णय के एक साल बाद जापान टोबैको ने कारोबारी मॉडल टिकाउ न होने का हवाला देते हुए अपना कारोबार समेट लिया था। हालांकि फिलिप मॉरिस भारतीय बाजार में मौजूद रही और अपने कारोबार के परिचालन के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार किया। मई 2009 से जनवरी 2018 के दौरान कंपनी के दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ है। एफडीआई पर रोक लगाए जाने से एक साल पहले उसने भारत की कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ एक विशेष करार किया था ताकि विश्व प्रसिद्ध मार्लबोरो सिगरेट का स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जा सके। *रॉयटर्स*

टिकी रह सकती है मिडकैप शेयरों में तेजी : इलारा

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 6 मार्च

इलारा कैपिटल ने एक नोट में कहा है कि मिडकैप शेयरों में आई हालिया तेजी टिकी रह सकती है क्योंकि मूल्यांकन बेहतर हैं और इसमें सुधार की गुंजाइश है। ब्रोकरेज के मुताबिक, लार्ज और मिडकैप के बीच मूल्यांकन का अंतर हाल में ऐतिहासिक तौर पर निचले स्तर पर चला गया था, जो मिडकैप को कम आकर्षक बनाता था।

इलारा कैपिटल के शोध प्रमुख रवि मुत्थुकृष्णन ने निवेशकों को भेजे नोट में कहा है, हमारा मानना है कि मिडकैप शेयरों के प्रदर्शन में सुधार के लिहाज से इन स्तरों पर मूल्यांकन बेहतर है, खास तौर से अच्छी गुणवत्ता वाले मिडकैप शेयरों में, जिन पर काफी चोट पड़ी है। बुधवार को मिडकैप व स्मॉलकैप शेयरों में तेजी जारी रही और मिडकैप 100 इंडेक्स 0.6 फीसदी चढ़ा जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई। एक दिन पहले स्मॉलकैप इंडेक्स में पांच महीने में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। छोटी कंपनियों के शेयरों में उछाल एक साल तक कमजोर प्रदर्शन के बाद देखने को मिली। नोट में कहा गया है, मिडकैप और लार्जकैप के बीच एक साल के रिटर्न (रोलिंग) का अंतर 22 फीसदी के नकारात्मक स्तर पर पहुंच गया था जबकि इसका औसत 4.4 फीसदी रहा है।

इलारा का मानना है कि निफ्टी मिडकैप वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2021 के बीच आय में 22 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि की दर से बढ़ोतरी दर्ज करेगा। आय में बढ़ोतरी को कच्चे तेल व जिंसों की स्थिर कीमत, उपभोग के मजबूत परिदृश्य से सहारा मिलेगा। आय में मजबूत बढ़ोतरी का अनुमान ठोस फंडामेंटल का सहारा देता है। ब्रोकरेज ने हालांकि अल्पावधि में उच्च उतारचढ़ाव की संभावना से इनकार नहीं किया।

ग्लेनमार्क ने इनोवेटिव बिजनेस का सीईओ नियुक्त किया

हाल में अमेरिकी इनोवेटिव बिजनेस को अलग कर एक कंपनी के दायरे में लाने का फैसला करने वाली दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने नोवार्तिस के दिग्गज एलेसांड्रो रीवा को सीईओ नियुक्त किया है। ग्लेनमार्क के इनोवेशन कारोबार के सीईओ के तौर पर उनकी नियुक्ति 2 अप्रैल से प्रभावी होगी। फरवरी में ग्लेनमार्क ने कहा था कि निदेशक मंडल ने सैद्धांतिक तौर पर इनोवेशन कारोबार को अलग कर एक कंपनी के दायरे में लाने को मंजूरी दे दी है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में होगा। द पारामुस कंपनी ग्लेनमार्क की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक होगी और सीईओ रीवा, प्रबंधन टीम और स्वतंत्र निदेशक मंडल के नेतृत्व में परिचालन करेगी। *बीएस*

नए लेखा मानक पर बैंक चाहे मोहलत

पृष्ठ-1 का शेष

बहुराष्ट्रीय कंसल्टेंसी में अकाउंटिंग एडवाइजरी के प्रमुख ने कहा, 'नए लेखा मानक को एक साल टालने के बाद कई बैंकों ने सॉफ्टवेयर और प्रणाली में बदलाव के काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।' उन्होंने कहा कि इस तरह के बदलाव में कम से कम एक तिमाही का वक्त लग सकता है।वर्ष 2016 में आरबीआई ने भारतीय लेखा मानक के लिए अपने प्रारंभिक दिशानिर्देश में बैंकों से कहा था कि वह दोनों लेखा प्रारूप के बीच अंतर का विश्लेषण करें। बैंकों ने इसके बाद भारतीय लेखा मानक के आधार पर समानांतर लेखा मूल्यांकन किया।

बैंकों को भारतीय लेखा मानक के तहत प्रस्तावित तुलना के लिए पिछले साल के वित्तीय विवरण के साथ ही अप्रैल 19 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। बैंकिंग उद्योग की लॉबीइंग निकाय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने कहा कि निकट भविष्य में बैंकिंग नियामक द्वारा अंतिम नियम लेकर आने की संभावना कम ही है।'

आईबीए का कहना है कि भारतीय लेखा मानक के लिए दिशानिर्देश की अभी घोषणा नहीं की गई है। इससे संकेत मिलता है कि आरबीआई इसे टाल सकता है। पिछले साल कुछ बड़े बैंकों को पहले नए लेखा मानक अपनाने को कहा गया था लेकिन यह परवान नहीं चढ़ सका।

जवाबी कार्रवाई के पक्ष में नहीं भारत

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 6 मार्च

अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी तरजीही कारोबारी व्यवस्था के तहत वहां के बाजार में पहुंचने वाले शुल्क रहित भारतीय उत्पादों को इससे बाहर कर दिया है। अमेरिका के इस निर्णय के बावजूद भारत उस पर जवाबी कार्रवाई के तहत प्रतिक्रियात्मक शुल्क का नया सेट लाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि आगामी अप्रैल से सरकार अमेरिका से आयात होने वाले 29 प्रमुख उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। भारत ने इसकी घोषणा पिछले वर्ष ही की थी जिसके बाद से इस निर्णय को अब तक रिकॉर्ड छह बार टाला जा चुका है।

महीनों से हो रही चर्चा पर विराम लगाते हुए सोमवार की रात अमेरिका ने अपने सबसे बड़ी तरजीही कारोबारी व्यवस्था के तहत वहां के बाजार में भेजे जाने वाले शुल्क रहित भारत के उत्पादों को इस योजना से बाहर कर दिया। लेकिन भारत ने इसके प्रभाव को नजरअंदाज किया और इस लड़ाई से दूर ही रहने इच्छा जताई है। बहरहाल तरजीह की कारोबारी व्यवस्था (जीएसपी) के तहत लाभों को समाप्त करने में कम से कम 60 दिन लगेंगे। बुधवार को वाणिज्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है लेकिन शुल्कों के नए सेट से मुद्दा केवल जटिल ही होगा। यदि हमने अपने दो सबसे करीबी वैश्विक कारोबारी सहयोगियों के बीच एक वर्ष तक कारोबारी तनाव को झेला है, तो ऐसे में नए संकट के बावजूद हम दूसरे साल भी तनाव का सामना कर सकते हैं।' मीडिया रिपोर्टों से यह बात सामने आई है कि सरकार अमेरिका से आयात होने वाले ऐसे वस्तुओं की सूची बना रहा है जिस पर उच्चतर शुल्क लगाए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'जीएसपी पर चर्चा काफी लंबे समय से हो रही थी और ट्रंप प्रशासन इस सूची से दूसरे देशों को बाहर कर रहा है। लेकिन अब जिस शुल्क पर प्रश्न उठाया जा रहा है उसकी घोषणा पिछले वर्ष की गई थी और दोनों देशों के उद्योगों के पास कारोबार में संभावित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय था।' जीएसपी के तहत भारत सबसे बड़ा लाभार्थी देश है। अमेरिका का तरजीही कारोबार कार्यक्रम सबसे बड़ा और सबसे पुराना है जिसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर विकासशील देशों के हजारों उत्पादों का अमेरिका में शुल्क रहित आयात करने के लिए तैयार की गई थी।

एक दूसरे अधिकारी ने कहा, 'हालांकि, यदि बातचीत में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है तो हम पहले अधिसूचित किए गए उच्चतर शुल्क लगाएंगे। लेकिन इसे जीएसपी मुद्दे के बदले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि इस पर निर्णय बहुत पहले लिया गया था।'

असल में इस शुल्क वृद्धि को 28 जून, 2018 को लागू किया जाना था लेकिन भारत सरकार की ओर से इस शुल्क वृद्धि को बार बार टाला गया और अब 1 अप्रैल से इसके प्रभावी होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए जाने के बावजूद शुल्क को बार बार स्थगित किया गया। इस बीच अमेरिका के साथ चार प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता इस मुद्दे का हल निकालने में विफल रही।

भारत और अन्य देशों से आयात किए जाने वाले इस्पात और एल्युमीनियम पर अमेरिकी प्रशासन द्वारा एकतरफा शुल्क वृद्धि के जवाब में भारत ने अपने यहां अमेरिका से आयात किए जाने वाले सेब, बादाम, अखरोट आदि ज्यादातर कृषि उत्पादों और कुछ औद्योगिक उत्पादों पर 50 फीसदी तक उच्च शुल्क लगाने की घोषणा की थी।

इन सामानों पर लगेगा ज्यादा शुल्क

वस्तु	आयात की राशि**
बादाम	69.65
प्रयोगशाला अभिकर्मक*	14.937
फॉस्फोरिक अम्ल	11.038
सेब	10.718
फाउंड्री मोल्ड्स के लिए बांइडर	9.353
अखरोट	3.816
काबूली चना	3.263
आर्टेमिया (ब्राइन श्रिम्प)	3.088
मसूर की दाल	1.88
800 सीसी से उपर की मोटरसाइकल	1.061
विभिन्न प्रकार के लौह और इस्पात	8.933
लोहा और इस्पात से बने सामान	14.971
सभी वस्तुओं के आयात का कुल मुल्य	153.194

स्रोतः वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

नोट*: नियंत्रित रासायनिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है शुल्क वृद्धि का अन्य मदों सहित पूरी सूची के चलते आंकड़ों को नहीं जोड़ा गया है **2017-18 में आयात की राशि (करोड़ डॉलर में)

बिजली क्षेत्र ने रखा अपना पक्ष

आशिष आर्यन
नई दिल्ली, 6 मार्च

बिजली कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 12 फरवरी 2018 की अधिसूचना को लेकर उच्चतम न्यायालय में कहा कि यह नियम 'एक लाठी से सबको हांकने' जैसा है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से समाधान न हो पा रही बड़ी गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) को लेकर दिवाला याचिकाएं दायर करने को कहा था।

बिजली कंपनियों की तरफ से न्यायालय में पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कर्ज लेने वालों, कर्ज का भुगतान न कर पाने की वजहों, या क्षेत्र को प्रभावित करने वाली बाहरी वजहों को लेकर कोई अंतर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अधिसूचना से बैंकों का विवेकाधीन अधिकार भी छीन लिया गया, जिसके तहत वे गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में खुद फैसला कर सकते थे।

न्यायमूर्ति रोहिंटन फाली नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत शरण के दो न्यायधीशों का पीठ ममले की सुनवाई कर रहा है, जो बिजली, चीनी और शिपिंग कंपनियों ने 12 फरवरी की रिजर्व बैंक की अधिसूचना के खिलाफ दायर किया है। पिछले साल 12 फरवरी को रिजर्व बैंक ने बैंकों व कर्ज देने वाले अन्य वित्तीय संस्थानों से कहा था कि दबाव वाले बड़े खातों को लेकर या तो वे समाधान योजना लागू करें या उनके खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में याचिका दायर करें। एस्सार पावर, जीएमआर एनर्जी, केएसके एनर्जी और रत्तन इंडिया पावर के साथ एसोसिएशन आफ पावर प्रोड्यूसर्स (एपीपी) और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने इस अधिसूचना के खिलाफ उस समय शीर्ष न्यायायल में याचिका दायर की, जब इलाहाबाद ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बिजली कंपनियों ने आज कहा कि उनके मामले में आपूर्ति और मांग दोनों ही नियामकों की नजर में थी, ऐसे में बिजली क्षेत्र को रिजर्व बैंक की अधिसूचना से छूट मिलनी चाहिए। बिजली कंपनियों की ओर से न्यायालय में पेश वकील ने कहा, 'आपूर्ति पक्ष को देखें तो कोयले की कमी थी। हम कोयला कैसे पा सकते हैं? और अगर मुझे कोयला मिल जाता है तो मुझे लिंकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह अलग सवाल है। वहीं मांग पक्ष को देखें तो हम आपना शुल्क नहीं बढ़ा सकते। अगर हम ऐसा करने के लिए नियामक से संपर्क साधते हैं तो इसमें कम से कम 2-3 साल लगते हैं।'

ब्रांड बाजार में राजनीति

पृष्ठ 1 का शेष

कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी उनकी समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के कांग्रेसी नेता मिलिंद देवड़ा प्रचार से जुड़ी टीम में शामिल हैं। दूसरी ओर भाजपा में प्रचार की रूपरेखा की जिम्मेदारी अध्यक्ष अमित शाह और पीयूष गोयल संभाल रहे हैं।

ब्रांडबिल्डिंग.कॉम के संस्थापक अंबी परमेश्वरन कहते हैं, 'भाजपा के प्रचार में पिछली बार बदलाव पर जोर था जबकि इस बार प्रचार के केंद्र में सरकार की निरंतरता रहेगी। इसलिए सत्तारूढ़ दल का जोर अपनी उपलब्धियों के प्रचार पर होगा जबकि विपक्षी दल लोगों को पिछले पांच साल में हुई परेशानी और चुनौतियों को मुद्दा बनाएगी।'

कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि पिछले एक महीने में भाजपा ने सरकार के विज्ञापनों में उसकी विभिन्न योजनाओं का प्रचार किया है। इनमें उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया आदि शामिल हैं। मोदी ने सभी सरकारी विज्ञापनों को एक थीम के तहत लाने के लिए कुछ दिन पहले 'नामुमकिन अब मुमकिन है' टैगलाइन जारी की थी।

सूत्रों के मुताबिक पिछले एक महीने के दौरान केंद्र और भाजपा शासित राज्यों के विज्ञापनों पर कम से कम 600-700 करोड़ रुपये खर्च हुए होंगे क्योंकि यह चरण मतदाताओं का ध्यान खींचने के लिए बहुत अहम है। विशेषज्ञों के मुताबिक दूसरे चरण में भाजपा को जोर इस मुहिम को मजबूत करने की होगी।

चीनी खाने से नहीं होता मधुमेह!

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 6 मार्च

भारत को विश्व की मधुमेह की राजधानी बनाने के लिए क्या सिर्फ चीनी जिम्मेदार है? चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी को अनावश्यक रूप से इस विवाद में घसीटा जाता है कि बढ़ते मधुमेह की वजह चीनी है, जबकि इसके लिए बदलती जीवन शैली और शहरीकरण की प्रमुख भूमिका है।

देश की निजी चीनी मिलों के प्रमुख संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आईएसएमए) की ओर से आयोजित चीनी और स्वास्थ्य को लेकर आयोजित एक सेमीनार में उद्योग जगत के लोगों ने कहा कि 2,000 और 2016 बीच देश में मधुमेह के मामलों में सालाना 6.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि इस दौरान प्रति व्यक्ति चीनी की खपत में महज 1.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

आईएसएमए की कवायद ऐसे समय में चीनी के स्वास्थ्य संबंधी लाभ गिनाने की है, जब भारत में 2018-19 चीनी सत्र (अक्टूबर-नवंबर) के बीच चीनी का उत्पादन 300 से 310 टन जबकि देश में खपत 260 लाख टन रहने का अनुमान है। पिछले साल के बचे स्टॉक और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम उठान की वजह से चीनी का स्टॉक 2018-19 चीनी सत्र के अंत तक 110 लाख टन से ज्यादा बचे रहने की संभावना है। तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी की घरेलू खुदरा खपत में वृद्धि दर कम रहना अतिरिक्त स्टॉक की एक प्रमुख वजह है। आईएसएमए के महाप्रबंधन अविनाश वर्मा ने कहा, 'भारत में सालाना चीनी की खपत प्रति व्यक्ति 18.4 किलो है, जो दुनिया में सबसे कम है। यह पाकिस्तान व श्रीलंका से भी कम है। इसके बावजूद हमारे यहां मधुमेह तेजी से फैल रहा है। इससे लगता है कि समस्या की वजह कुछ और है, न कि चीनी की खपत।'

उन्होंने कहा कि आज चीनी की खपत को लेकर दो बड़े मिथक प्रचलित हैं। पहला- इसकी वजह से मधुमेह होता है और दूसरा- इसकी वजह से बच्चों और बड़ों के दांत खराब होते हैं। अगर दांत खराब होने की बात करें तो अध्ययन एवं शोध से पता चलता है कि खाने में एसिड और पीएच वैल्यू की वजह से ऐसा होता है, जो कि चीनी में सामान्य माना जाता है। अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे है तो उसे एसिडिक माना जाता है और अगर इससे ज्यादा है तो उसे एल्कलाइन माना जाता है। वर्मा ने कहा, 'रसदार फलों जैसे नींबू, अचार, टमाटर और कॉफी में कम पीएच स्तर होता है और इस तरह से ये चीनी से ज्यादा एसिडिक हैं। इस तरह से देखें तो दांत खराब होने की वजह चीनी नहीं है। हालांकि यह सही है कि जब खाना दांत से चिपक जाता है तो यह एसिडिक हो जाता है। अगर दांत नियमित रूप से साफ किया जाए तो उन्हें खराब होने से रोका जा सकता है।'

इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही जानी मानी पोषण विशेषज्ञ इशि खोसला ने कहा कि सिर्फ चीनी खाने से मधुमेह नहीं होता बल्कि अगर बहुत ज्यादा चीनी खाया जाए तो निश्चित रूप से यह मधुमेह की वजह बन सकती है।

दीवाली पर रिलायंस ई-कॉमर्स

पृष्ठ 1 का शेष...

एक सूत्र ने बताया कि पहले कदम के तौर पर रिलायंस असंगठित क्षेत्र के स्टोरों और कुछ बड़े रिटेलरों के यहां जियो ब्रांड के प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीनें लगा रही हैं। इसका मकसद लेनदेन के डेटा को जियो सिस्टम के साथ जोड़ना है।

आरआईएल ने पिछले महीने ही अपने ई-कॉमर्स योजना का ऐलाना किया था। गांधी नगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में अंबानी ने कहा था, 'रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल एक अनूठा नया कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करेगी, जो 12 लाख छोटे रिटेलरों को सक्षम बनाएगा।' इसके साथ आरआईएल टेलीकॉम, मीडिया और कॉमर्स को आपस में मिलाने की तैयारी में है। इससे मौजूदा कंपनियों में खलबली है। एमेजॉन ने भारतीय कारोबार में 5 अरब डॉलर झोंकने की घोषणा की है जबकि वॉलमार्ट ने पिछले साल फ्लिपकार्ट में 16 अरब डॉलर के सौदे में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदी थी।

विदेशी बनाम घरेलू की इस लड़ाई में आरआईएल फायदे की स्थिति में रह सकती है। उदाहरण के लिए आरआईएल अपना खुद का सामान ऑनलाइन बेच सकती है लेकिन विदेशी कंपनियों के मालिकाना हक वाली कंपनियों को यह अनुमति नहीं है। दुनियाभर में इंवेंट्री मॉडल की कामयाबी की वजह यह है कि कंपनी जो माल बेचती है, उस पर उसका नियंत्रण रहता है। रिलायंस को खुदरा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी का फायदा मिलेगा। रिलायंस रिटेल के 6,500 शहरों में 10,000 से अधिक स्टोर हैं जिनमें कपड़ों से लेकर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान और डिब्बाबंद सामान बेचा जा रहा है। साथ ही उसकी टेलीकॉम क्षेत्र में भी मौजूदगी है और उसके इंटरनेट उपयोक्ताओं की संख्या 28 करोड़ है। आरआईएल की अभी ई-कॉमर्स क्षेत्र में सीमित मौजूदगी है। कंपनी फैशनी साइट एजियो.कॉम का संचालन करती है जो 2016 में शुरू हुई थी। साथ ही वह इलेक्ट्रॉनिक चेन रिलायंस डिजिटल का भी ऑनलाइन स्टोर फ्रंट है।

विश्लेषकों का कहना है कि जियो ने दूरसंचार क्षेत्र में जो खलबली मचाई थी उसकी पुनरावृत्ति ई-कॉमर्स क्षेत्र में भी देखने को मिल सकती है। मोबाइल के मोर्चे पर आरआईएल 5जी सेवाओं पर 40 अरब डॉलर खर्च कर चुकी है।

बीएस सूडोकू 3375 | परिणाम संख्या 3374

		6		2	7		4	
		5						8
3			5		8	7		
	9			3		8		
		2	6		5	1		
		1		8			5	
		8	9		2			1
2						5		
	5		7	4		6		

7	6	1	9	4	5	3	8	2
5	3	4	8	2	6	7	9	1
9	2	8	3	7	1	5	6	4
1	8	3	2	9	7	6	4	5
2	7	5	6	3	4	9	1	8
4	9	6	1	5	8	2	3	7
3	1	2	7	8	9	4	5	6
6	4	9	5	1	2	8	7	3
8	5	7	4	6	3	1	2	9

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसान ★☆☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 1930/1940, जौ 1800/1810, चावल मसूरी 2300/2350, चावल मोटा 2175/2225, सरसों नई 3300/3360, तिल सफेद 11200/11400, सोया (टीन) 1200/1250, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1270/1380,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 1950/1960, गेहूं शरबती 2500/2550, चावल शरबती सेला 3900/3950, स्टीम 4600/4700, लालमती 3150/3250, चावल (सोना) 2750/2825

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1765, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.) 2080, फ्लैक 1880, डीएमओ 1200, टरपीन लैस बोल्ड 2100

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): चाकू 940/1010, खुरपा 920/945, लड्डू 960/1015, रसकट 780/790, शक्कर 1000/1015, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3175, देवबंद 3120,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3350/3450, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 850/880, तिलहनः सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 3650, खलः सरसों 2000/2100,

जयपुर
अनाजः चावल डीबी 6500/6600, गेहूं (मिल) 1980/1990, मक्की 1980/2000, बाजरा 1840/1850, जौ 1750, ग्वार लूज 3900/3950, ज्वार कैटलफीड 1300/1325, सरसों(मिल पहुंच) 3890/3900,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 1980/1990, ग्वार 4050/4100, जौ 1880/1890, सरसों लूज 3500/3550

जोधपुर
गेहूं 1950/2000, जौ 1775/1800, पोपकोन मक्की 3700/3800, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4200/4250, ग्वारगम 8300/8400, बाजरा (गुजरात) 1900/1950, बाजरा (जयपुर) 1850/1875, चना 3800/3900, काबली चना 5000/6200, मूंग 5000/5300,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्वि .): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)115, राइसब्रान (अखाद्य) 113, खल सरसों 1710, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 970, लाल 970, कंटीन्यूअस 1080,

लुधियाना
दाल-दलहनः राजमां चित्रा 8500/9000, अरहर दाल 6300/6900, उड़द साबुत 5500/6300, उड़द धोया 6000/7000, छिलका 6000/6500, दाल मसूर 5100/5400, चनादाल 5400/5500,

अमृतसर
चावलः बासमती (1121 नं.) स्टीम 7400/7500, सेला 6900/6950, शरबती साधारण सेला 4000/4100, शरबती स्टीम 4700/4750, धानः शरबती 2175/2200, बासमती 1121 धान 3625/3630, धान (1509) 3090/3100, पीआर-11-2240/2250, गुड़ (क्विं): लड्डू मंगलौर 2640/2675, देशी पंजाब 2675/2700,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4380/4470, हरियाणा 4350/4450, राजस्थान 4325/4395, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2380/2480, सरसों खल 1830/1835,

फाजिल्का
गेहूं 1925/1930, सरसों नई 3300/3350, रुई (प्रति मन): (जे-34) 4380/4450,कपास देशी 4450/4475, कपास नरमा (क्विं.) 5450/5550,

जालंधर
गेहूं दड़ा 1975/1980, चावल परमल कच्चा 2500/2525, से ला 2380/2420, मक्की 2100/2110, दाल उड़द छिलका 6300/6900, चना देशी 4750/4850, दाल चना 5050/5150, काबली चना 5500/6900, राजमां चित्रा पुणे 6600/8000, चीन 8300/8600, शर्मिली 6500/6700,

करनाल
गेहूं दड़ा 1935/1940, बासमती चावल 7500/7600, धान 1121 नं. 3600/3650, पूसा 1509 धान 3140/3150, शरबती धान 2300/2310, सेला (1509 नं.) चावल 6300/6350, स्टीम 7400/7500,

हिसार
ग्वार 3950/4000, सरसों 3550/3575, गेहूं 1980/1990,

जींद
जीएसटी अतिरिक्तः गेहूं 1925/1950, आटा (प्रति 44 किलो) 980/990, मैदा 1080/1090, देशी घी (एक ली/जार) 300/360, रिफाइंड (टीन) 1290/1330,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्तः सरसों 3650/3700, खल बिनौला मोटी 2300/2400, बिनौला 2500/3000, सरसों तेल 8050/8100, गेहूं 1900/1950, ग्वार 3950/4000, जौ 1400/1425, नरमा 5450/5500, बाजरा 1775/1800

एनएनएस

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 17

अरावली को बचाएं

हरियाणा सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण से संबंधित कानून में संशोधन करके इस पर्वत श्रृंखला के एक अहम हिस्से को वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध करा दिया है। ऐसा करके राज्य सरकार ने न केवल अपने ही कदम से उपजी विभिन्न जटिलताओं की अनदेखी की है बल्कि उसने सर्वोच्च न्यायालय की निषेधाज्ञा का भी स्पष्ट उल्लंघन किया है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पर्यावास को बचाने के लिए इन पहाड़ियों तथा आसपास के क्षेत्र में तमाम गैर-वानिकी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था। ब्रिटिश शासन ने सन 1900 में ही इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पंजाब लैंड प्रीजर्वेशन ऐक्ट (पीएलपीए) का गठन किया था। अब इन पहाड़ियों के एक बड़े हिस्से का वन होने का दर्जा छीना जा रहा है। पर्यावरणविदों का मानना है कि यह संशोधन अरावली पर्वत श्रृंखला के अंत का फरमान है। अच्छी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल इसके प्रवर्तन पर रोक लगाई और इस कदम को निंदा योग्य बताया है।

692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली है। यह भारी प्रदूषण वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है। इसके अलावा यह थार मरुस्थल के विरुद्ध एक प्राकृतिक कवच का काम करती है।

अरावली के एक अहम हिस्से का वन का दर्जा छीने जाने की एक स्वाभाविक वजह अवैध अतिक्रमण को वैधता प्रदान करना और अरावली के वनों का अचल संपत्ति, खनन और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के रूप में दुरुपयोग किया जाना भी है। ये गतिविधियां सन 1970 से ही जोर पकड़ रही हैं। इस पर्वत श्रृंखला पर लाखों की तादाद में मकान, वाणिज्यिक इमारतें और उद्योग-धंधे पहले ही शुरू हो चुके हैं। अरावली पहाड़ियों का करीब 30 फीसदी हिस्सा फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में आता है और अब से पहले यह पीएलपीए के अधीन संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित था। अकेले फरीदाबाद में कम से कम पांच वाणिज्यिक संस्थाएं, तीन अवैध कॉलोनियां और 140 से अधिक निजी फार्म हाउस तथा बैंक्वेट हॉल तथा दो शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं।

भारतीय वन्यजीव संस्थान के 2017 के एक अध्ययन में कहा गया है कि अरावली पहाड़ियों का हरियाणा में आने वाला हिस्सा देश का सबसे कमजोर वन क्षेत्र है। तेज गति से वनों का खात्मा और वहां हो रही विकास संबंधी गतिविधियां इस विशिष्ट भूक्षेत्र को नए सिरे से नष्ट कर रही हैं। अरावली के राजस्थान में आने वाले हिस्से में भी हालत कोई खास बेहतर नहीं है। अरावली के इस क्षेत्र में आने वाली 128 पहाड़ियों में से 31 पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। इसके लिए भू माफिया और खनन माफिया जिम्मेदार हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का पर्यावास की दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व है। वनों को नष्ट होने से रोकने के अलावा यह राजस्थान से चलने वाली धूल भरी हवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती है और पहले ही खराब गुणवत्ता वाली हवा को कुछ हद तक बचाती है। इस क्षेत्र के भूजल रिचार्ज में भी इसकी अहम भूमिका है। इतना ही नहीं, यह कई नदियों और जलधाराओं का स्रोत भी है। साबरमती, लूनी, चंबल और कृष्णावती इनमें प्रमुख नदियां हैं। दमदमा, धौज, बड़खल और सूरजकुंड जैसी झीलों का जलागम क्षेत्र भी यही पर्वत श्रृंखला है। इन पहाड़ियों में जबरदस्त जैव विविधता है। यहां अनेक प्रकार के पौधे, जीव-जंतु और पक्षी पाए जाते हैं। हरियाणा 3.59 फीसदी वन क्षेत्र के साथ देश में सबसे कम हरियाली वाला राज्य है।

ऐसे में वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कदम का बचाव करना संभव नहीं है। उम्मीद है कि राज्य सरकार पर्यावरणविदों तथा सर्वोच्च न्यायालय की बात सुनेगी और अधिनियम में किए गए संशोधन को खत्म करेगी। उसे अरावली वन क्षेत्र को बचाने और बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

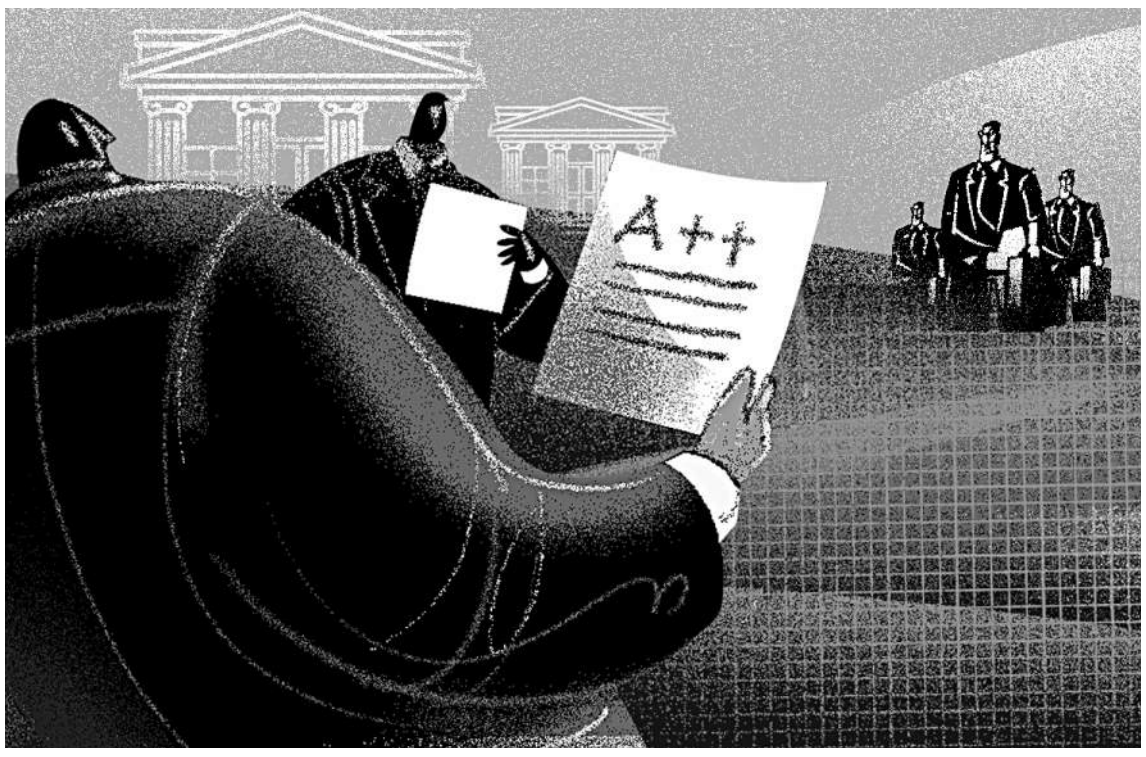

अजय मोहंती

कैसे दूर हो देश में रेटिंग का संकट

हाल के दिनों में रेटिंग एजेंसियों को लेकर जो भी नकारात्मक खबरें आई हैं उनके पीछे वजह यह है कि उन पर रेटिंग को बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत करने का दबाव होता है। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं तमाल बंद्योपाध्याय

एक राजा था जिसे सड़कों पर चलना अच्छा लगता था लेकिन वह चाहता था कि उसके पैर गंदे न हों। घोषणा की गई कि जो व्यक्ति इस समस्या का समाधान खोजेगा, उसे भारी भरकम इनाम से नवाजा जाएगा। पहला व्यक्ति हजारों झाड़ुओं के साथ आया। झाड़ू से पूरे साम्राज्य के ऊपर धूल के बादल छा गए और राजा बीमार पड़ गया। दूसरे व्यक्ति ने लाखों भेड़ों को मार कर उनका चमड़ा सड़क को ढकने के लिए इस्तेमाल किया लेकिन इससे आधा मार्ग भी नहीं ढका जा सका। आखिरकार एक मोची दरबार में आया, उसने राजा के पैरों की नाप ली और उनके लिए एक जोड़ी सैंडल बनाए। अब राजा आराम से सड़क पर घूम सकता था और उसके पैर भी गंदे नहीं होते थे।

देश में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की कमियों से जूझ रहे निवेशकों की समस्या हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक के बाद एक कारोबारी घरानों के डिफॉल्ट ने कर्जदारों और बॉन्डधारकों को बुरी तरह प्रभावित किया है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कंपनियों की स्थिति को लेकर निवेशकों को भ्रमित किया।

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस कंपनी की रेटिंग एजेंसी इक्रा ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) की रेटिंग को एकबारगी ही निवेश श्रेणी से खराब में, एए प्लस से डी में बदल दिया। कंपनी को सन 1997 में एएए श्रेणी मिली हुई थी और इक्रा, इंडिया रेटिंग ऐंड रिसर्च और केयर रेटिंग, तीनों ने उसे एएए श्रेणी दी थी। एक अन्य एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया को हाल में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आचार संहिता का पालन न करने के लिए दंडित किया है। इसने दो कंपनियों के डिफॉल्ट को चिह्नित करने में देरी की थी।

देश में रेटिंग की इस गड़बड़ी में सुधार के लिए इसके नियमन की समीक्षा आवश्यक है। सुझाव यह भी है कि इनके लिए निवेशक के भुगतान वाला मॉडल अपनाया जाए। फिलहाल भुगतान कर्जदाता करते हैं। लंबे जुड़ाव के बदले इनमें चक्रीय बदलाव, कम से कम दो या अधिक एजेंसियों द्वारा अनिवार्य रेटिंग आदि के सुझाव भी हैं। खासतौर पर तब जबकि ऋण का आकार 100 करोड़ रुपये से अधिक हो। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए इनकी तादाद बढ़ाने की बात भी कही गई है।

अमेरिका में देश क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं लेकिन वहां स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स, मूडीज और फिच का वर्चस्व है। हमारे यहां सात एजेंसियां हैं लेकिन यहां भी क्रिसिल, केयर और इक्रा के पास रेटिंग कारोबार का 80 फीसदी है। बाकी का काम अन्य एजेंसियों में बंटा हुआ है।

सैद्धांतिक रूप से देखें तो दो वजहों से प्रतिस्पर्धा का स्वागत किया जाना चाहिए। एक तो शुल्क में कमी आएगी और दूसरा रेटिंग में सुधार होगा। शुल्क तो पहले ही कम है। बैंक ऋण के लिए रेटिंग का ये एजेंसियां 40,000 रुपये और ऋण उपायों की रेटिंग के लिए कुल ऋण के कुछ आधार अंक, अधिकतम 10 आधार अंक तक लेती हैं। एक आधार अंक प्रतिशत का सौवां हिस्सा होता है।

गुणवत्ता सुधार के बजाय अधिक रेटिंग एजेंसी कई बार मानक कमजोर करने का काम भी करती हैं। कुछ एजेंसियों पर यह संदेह किया गया कि वे कारोबार के लिए रेटिंग से समझौता करती हैं। ऐसे में निवेशक द्वारा भुगतान का मॉडल भी सही काम नहीं करेगा क्योंकि निवेशक और रेटिंग करने वालों में गठजोड़ हो सकता है।

अधिकांश निवेशक, खासतौर पर म्युचुअल फंड अक्सर रेटिंग को औपचारिकता मानते हैं। वे रेटिंग में गिरावट को नापसंद करते हैं क्योंकि इसका असर मूल्यांकन पर पता है और निवेश का शुद्ध मूल्य कम होता है। अगर निवेशकों को ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पैसे खर्च करने होंगे तो वे रेटिंग एजेंसी को भुगतान क्यों करेंगे? बल्कि वे यही पैसा तथाकथित जांच परख की प्रक्रिया में व्यय करेंगे।

राजा के पैरों को धूल से बचाने वाले मोची की तरह सबसे सहज उपाय यही है कि डेट बाजार का गठन किया जाए। अभी बीमा और प्रोविडेंट फंड जैसे दीर्घकालिक निवेशक अपेक्षाकृत कमतर जगहों पर निवेश नहीं करते क्योंकि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकार एए श्रेणी से नीचे बहुत कम निवेश की इजाजत देते हैं।

बैंक भी ऐसे कर्जदार को पैसा देने को उत्सुक नहीं हैं जिसकी रेटिंग कम से कम बीबीबी न हो जो निवेश श्रेणी के लिए न्यूनतम है। ऐसे ऋण के लिए जोखिम अधिक होता है।

संक्षेप में कहें तो इसका हल उच्च प्रतिफल वाले बॉन्ड बाजार में निहित है। यहां निवेशक और बैंक अपने जोखिम का दांव लगा सकते हैं और कम रेटिंग वाले डेट प्रपत्र और निगमों के समक्ष जा सकते हैं। जब तक निवेश मानक शिथिल नहीं किए जाते तब तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उच्च रेटिंग देने के दबाव में रहेंगी। अमेरिकी बॉन्ड बाजार देश के जीडीपी का 120 फीसदी है। इसकी तुलना में भारतीय बॉन्ड बाजार जीडीपी का बमुश्किल 15 फीसदी है।

इन एजेंसियों द्वारा डिफॉल्ट को देर से पहचानने की एक वजह जीवंत आंकड़ों का न होना भी है। बैंकों को एक दिन के डिफॉल्ट के आंकड़े सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) को देना होता है। रेटिंग एजेंसियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। परंतु कई एजेंसियां इसका लाभ लेती हैं और जानबूझकर डिफॉल्ट को चिह्नित करने में देरी करती हैं। इसका फायदा जारीकर्ता को भी होता है और निवेशक को भी। अगर एजेंसियों को अद्यतन आंकड़ें मिलें तो वे जोखिम का बेहतर आकलन कर पाएंगी। अनदेखी करने पर उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए।

एसऐंडपी और मूडीज दोनों को 2008 में मॉर्गेज समर्थित प्रतिभूतियों की गुणवत्ता का सही आकलन न कर पाने पर दंडित किया गया था। इसके चलते ही 2008 का वित्तीय संकट आया था। 137 करोड़ डॉलर के जुर्माने के अलावा एसऐंडपी ने 12.5 करोड़ डॉलर की राशि कैलिफोर्निया पब्लिक एंप्लॉयीज रिटायरमेंट सिस्टम को तथा 8 करोड़ डॉलर की राशि प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग को चुकाई। मूडीज ने न्याय विभाग को 43.75 करोड़ रुपये का जुर्माना दिया और राज्यों तथा वॉशिंगटन डीसी को 42.63 करोड़ डॉलर की राशि चुकाई गई।

हमारे देश में सेबी इन एजेंसियों पर बमुश्किल 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाता है। भले ही संदर्भ अलग हों लेकिन यह जुर्माना किसी भी तरह नाकाफी है।

निवेशकों को भी रेटिंग को इतनी अधिक तवज्जो देनी बंद करनी होगी। उन्हें अन्य अहम संकेतकों पर भी नजर रखनी चाहिए।

(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक, लेखक एवं जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लि. के वरिष्ठ परामर्शदाता हैं)

नए भारत के बारे में सामरिक पूर्वानुमान लगा पाना कठिन

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

भारतीय वायुसेना का पकड़ा गया पायलट अब लौट चुका है, नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी में थोड़ी कमी आई है और भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि पुलवामा हमले जैसी एक और वारदात सीमापार तनाव का नया दौर शुरू कर सकती है। ऐसे में यह आकलन करना सही होगा कि भारत के हवाई हमले से सामरिक परिदृश्य में क्या कोई बदलाव आया है?

पहला, भारत के 'सामरिक संयम' के परित्याग से भारी बदलाव आया है। पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत को यह संदेश भेजते रहे कि संयम दिखाते हुए बातचीत से समाधान तलाशा जाए। इमरान ने भारत का एक मिग-21 विमान मार गिराने और एक पायलट को पकड़ने के बाद भी संयम बरतने की बात कही। अगले ही दिन इमरान ने 'शांति के लिए पहल' करते हुए पायलट को लौटाने की पेशकश कर दी। यह बात ध्यान रखनी होगी कि पाकिस्तान का नेता अचानक ही तर्कसंगत बातें करने लगा है। भारत का नेता तो ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। पाकिस्तान की 'सोची-समझी तर्कशून्यता' की रणनीति अब खत्म हो चुकी है। भारत के सामरिक संयम की जगह 'सुनिश्चित प्रतिरोध' ने ले ली है।

हालांकि इस बदलाव की गंभीरता का आकलन मुश्किल है। वर्ष 1947 से ही भारत ने पाकिस्तान के साथ हरेक संघर्ष में तर्कसंगत एवं जिम्मेदार पक्ष की भूमिका निभाई है। उसने अक्टूबर 1947 में कश्मीर में अपनी सेना तभी भेजी थी जब महाराजा हरि सिंह ने विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। वर्ष 1965 की शुरुआत में भारत ने कच्छ में पाकिस्तान की हरकत पर ऐसा संयम दिखाया कि राष्ट्रपति अयूब खान ने यह मान लिया कि कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के घुसने का बहुत प्रतिरोध नहीं होगा। वर्ष 1999 में भी करगिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के दौरान भारत ने ऐसा ही संयम दिखाया था। सीमापार आतंकवाद और उग्रवाद के लंबे दौर में भी भारत ने संयम का परिचय दिया था। वर्ष 2001-02 में संसद पर आतंकी हमला होने के बाद भारत ने अपनी सेना को सीमा पर तैनात करने के बाद भी विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस बुला लिया। जल्द ही भारत ने 'कोल्ड स्टार्ट' सिद्धांत अपनाया जिसमें सैन्यबलों को किसी भी उकसावे की स्थिति में पाकिस्तान में घुसने का प्रावधान है। लेकिन अग्रिम सीमा पर पाकिस्तानी सेना और परमाणु हथियारों की तैनाती ने भारतीय नीति-निर्माताओं के हाथ बांध दिए।

समूची अवधि में पाक सैन्य मुख्यालय ने भारत को यह अहसास दिलाने की कोशिश की है कि भारत की तरफ से किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब देते समय वह विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा। वह ऐसे संकेत भी देता रहा कि भारत को नहीं रोक पाने पर वह परमाणु हथियारों के भी इस्तेमाल से नहीं चूकेगा। हालांकि भारत ने परमाणु हमले की सूरत में व्यापक नाभिकीय प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाया हुआ है लेकिन पाकिस्तान में कोई भी नहीं मानता है कि भारत कभी ऐसा कदम उठाएगा।

लेकिन अब ये तमाम धारणाएं अतीत की बात हो चुकी हैं। भारत ने भी अब अपना पहले से कोई अनुमान न लगाए जा सकने वाला रुख दिखाने के साथ आतंकी हमला करने वालों को सबक सिखाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति जताई है। भारत जवाबी गोलीबारी और सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर वायु शक्ति और शायद नौसैनिक शक्ति जैसे विकल्पों के बारे में भी सोच सकता है। इससे पाकिस्तान की पुरानी मान्यताएं ध्वस्त हो चुकी हैं। भारत के ठिकानों पर हमले का उसे तगड़ा जवाब मिलने का डर है।

दूसरा, भारत को अपनी मंशा के साथ क्षमता भी दिखानी होगी। यह खेद का विषय है कि बालाकोट में आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। वायुसेना प्रमुख ने इस पर एतराज जताते हुए कहा है कि 'शवों की गिनती करना वायुसेना का काम नहीं है'। लेकिन विमान में लगे कैमरे, सैटेलाइट तस्वीरों, मानवरहित हवाई उपकरणों और जमीनी एजेंटों के जरिये इस नुकसान का आकलन इसलिए अहम है कि भारत पूरी दुनिया को ऐसे हमले करने की मंशा के साथ इसकी क्षमता रखने के बारे में भी दिखा सके। भारत के मिग-21 विमान द्वारा पाकिस्तान के उन्नत विमान एफ-16 को मार गिराए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। वैसे तकनीक के इस दौर में भी ऐसे सबूत नहीं पेश कर पाना चिंताजनक है।

जवाबी हमलों के रास्ते पर बढ़ने के लिए भारत को अपने सैन्य सिद्धांत, रणनीति और प्राथमिकता में भी उसे जगह देनी होगी। हम सीमापार दंडात्मक हमलों को प्राथमिकता देकर किसी उकसावे का भी संयमित तरीके से सामना करने की मजबूत क्षमता विकसित कर पाएंगे।

तीसरा और शायद सबसे अहम बिंदु, भारत यह याद रखे कि इस संकट की जड़ में भी पहले की तरह कश्मीर ही है। पिछले पांच वर्षों में कश्मीरी अवाम के भीतर विलगाव की भावना अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। अपना हिंदुत्ववाद पूरे देश में लागू करने की भाजपा की कोशिशों से घाटी के मुस्लिम उद्वेलित हैं। गोरक्षकों के हाथों मुसलमानों के मारे जाने, घरवापसी, सार्वजनिक स्थलों पर नमाज की मनाही और लव जिहाद को कश्मीरी आज द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को वैध ठहराने का जरिया बता रहे हैं।

ऐसी स्थिति में कश्मीरी अवाम के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है लेकिन सरकार कश्मीर विवाद को महज सुरक्षा का मसला मानकर चल रही है। पिछले पांच वर्षों में घाटी में हिंसा बढ़ी है और अब निहत्थे कश्मीरी भी सुरक्षाबलों के सामने खड़े होने लगे हैं। जब तक कश्मीर उबलता रहेगा, तब तक पुलवामा जैसे हमले दोबारा होने और पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। केवल बातचीत से ही इस आक्रोश को शांत किया जा सकता है।

कानाफूसी

रसगुल्ले पर कड़वाहट

अगर आपको लग रहा था कि रसगुल्ले को लेकर विवाद खत्म हो गया है तो ऐसा नहीं है। एक वर्ष पहले इस मिठाई को बंगाल के रसगुल्ले के रूप में जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग मिल गया था लेकिन अब ओडिशा के लघु उद्योग निगम ने सुधार याचिका दायर करते हुए मांग कर दी है कि इस मिठाई का जीआई टैग बदलकर इसे जगन्नाथ रसगुल्ला कर दिया जाए। इस मामले की सुनवाई जीआई रजिस्ट्री को अप्रैल में करनी है और उसने ओडिशा के संस्थान से कहा है कि वह अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज जमा करे। अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहता है तो याचिका अपने आप खारिज हो जाएगी। गौरतलब है कि जून 2015 से ही ओडिशा और बंगाल रसगुल्ले पर अपने-अपने दावे को लेकर उलझे हुए हैं।

शराब और नियम

पुणे में एक राजमार्ग पर स्थित एक होटल अपने सातवें माले पर स्थित रेस्तरां में तो शराब परोसता है लेकिन भूतल के रेस्तरां में शराब नहीं दी जाती। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के ट्वीट के मुताबिक जब एक अतिथि ने इस बारे में जानकारी चाही तो कहा गया कि सीढ़ियों के माध्यम से होटल की सातवीं मंजिल और राजमार्ग के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक है। दरअसल दिसंबर 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों पर रोक लगाने के लिए राजमार्ग से 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सात महीने बाद उसने स्पष्ट किया था कि यह प्रतिबंध शहर की सीमा में लागू नहीं होती। यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त होटल शहर की सीमा में आता है या नहीं और उसके मालिकों को इस छूट के बारे में जानकारी है या नहीं।

आपका पक्ष

कॉलेज प्लेसमेंट का गिरता स्तर

आज के दौर में प्रतिस्पर्धा एक आम धारणा बन चुकी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ अच्छा रोजगार पाने की आशा में युवा वर्ग परिस्थिति और क्षमता के हिसाब से छोटे-बड़े शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेते हैं। विद्यालयों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते बड़े और लोकप्रिय संस्थान अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दे रहे हैं और छात्रों को भविष्य सुरक्षित करने का वादा कर रहे हैं। देश के अधिकांश संस्थान अंतिम सत्र के दौरान होने वाले प्लेसमेंट और नौकरी का प्रलोभन देते हैं लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति बहुत गंभीर है। देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर बहुत अधिक हो गई है और सरकारों के पास इसका उचित और स्थायी इलाज संभव होता दिखाई नहीं दे रहा। निजी क्षेत्र में अनुभव को वरीयता दी जा रही है और छात्रों को शुरुआती स्तर पर नौकरियां तलाशने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैंपस

प्लेसमेंट में भी मिलने वाली नौकरियों में से अधिकांश में सालाना पैकेज बहुत कम होता है और किसी भी बड़े शहर में इस वेतन के साथ जीविकोपार्जन काफी मुश्किल होता है। कई बार छात्रों को केवल इसलिए उनके कौशल के हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। हमें इन परिस्थितियों का

शैक्षणिक संस्थानों को कैंपस प्लेसमेंट के लिए उचित मानक स्थापित करने चाहिए

स्थायी समाधान खोजना होगा। कई बार बड़ी कंपनियां नौकरी के नाम पर बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करके युवाओं के भविष्य को बांध लेती हैं। छात्रों को नौकरी के साथ मुफ्त खाना, आवास जैसे प्रलोभन दिए जाते हैं लेकिन वास्तविकता में स्थिति काफी अलग होती है। इस परिस्थिति से बचाने के लिए ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। नियुक्ति संबंधी मौजूदा कानूनी प्रावधानों का पालन सख्ती से करना होगा। साथ ही, कैंपस प्लेसमेंट आयोजित कराने वाले संस्थानों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभ्यर्थी को चाहिए कि वह धैर्यपूर्वक नौकरी की नियुक्ति शर्तों को पढ़कर तथा संबंधित कंपनी की पृष्ठभूमि पता करके ही नौकरी प्रस्ताव पर विचार करे।

ऋषभ देव पांडेय, कोरबा

बचे मामलों का जल्द हो समाधान

जीएसटी परिषद द्वारा हाल में रियल एस्टेट के लिए जीएसटी दरों में की गई कटौती निश्चित तौर पर मकानों की बिक्री बढ़ाएगी। लेकिन अभी भी इस उद्योग को राहत पहुंचाने वाले कुछ मामले छूट गए हैं। उम्मीद है कि जीएसटी परिषद इन मामलों को आगे शीघ्र सुलझाएगी। जीएसटी परिषद को किफायती मकानों की परिभाषा को और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए महानगर और गैर-महानगर के लिए किफायती मकानों की परिभाषा एक समान ना होकर व्यावहारिक आधार पर अलग-अलग होनी चाहिए। साथ ही बिल्डरों की लागत के बोझ को कम करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी देना चाहिए। भवन निर्माण सामग्री खासकर सीमेंट पर जीएसटी की 28 फीसदी दर काफी ज्यादा है। इसलिए इसमें कमी की जानी चाहिए। इससे न केवल बिल्डरों की लागत घटेगी, बल्कि खरीदारों को भी मकान खरीदने पर कम खर्च करना पड़ेगा। जीएसटी परिषद को आम जनता के साथ ही बिल्डरों के सामने आने वाली परेशानियों का भी समाधान करना चाहिए।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

सोयाबीन अनुदान योजना में निजी बाजार समितियां

बीएस संवाददाता
मुंबई, 6 मार्च

महाराष्ट्र में खरीफ सीजन 2016-17 के दौरान अक्टूबर से दिसंबर 2016 की अवधि में निजी बाजार समितियों और प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंस धारकों के यहां सोयाबीन बिक्री करने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 200 रुपये और प्रति किसान अधिकतम 25 क्विंटल पर अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 16 प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंस धारकों और 11 निजी बाजार लाइसेंस धारकों के पास सोयाबीन बिक्री करने वाले किसानों को मिलेगा। सोयाबीन अनुदान योजना में निजी बाजार समितियों का समावेश करने का यह निर्णय मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक लिया गया है।

सहकार और विपणन मंत्री सुभाष देशमुख ने कहा कि राज्य में खरीफ सीजन 2016-17 में सोयाबीन उत्पादन में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई थी। इससे बाजार में भारी मात्रा में सोयाबीन आने से भाव में कमी आई। सोयाबीन किसानों को आर्थिक मदद की दृष्टि से राज्य की कृषि उपज बाजार समितियों में अक्टूबर से दिसंबर 2016 की अवधि में सोयाबीन बिक्री करने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 200 रुपये और अधिकतम 25 क्विंटल प्रति किसान अनुदान देने का निर्णय लिया गया।

मासिक कोटा बढ़ने से चीनी में गिरावट

सरकार की ओर से मिलने वाले फायदे को कम कर देगी चीनी के दामों में आ रही गिरावट

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 6 मार्च

चीनी की कीमतों में लगातार गिरावट से सरकार द्वारा मिलों को दी गई मदद का लाभ कम हो जाएगा। सरकार ने मिलों को गन्ने के बढ़ते बकाये का भुगतान करने और इस मूल्य श्रृंखला में पूंजी उपलब्धता की स्थिति सुधारने के लिए मदद दी है।

सरकार ने मार्च 2019 के लिए 24.5 लाख टन चीनी के अब तक के सबसे अधिक मासिक कोटे की घोषणा की है। इसके बाद पिछले दो सप्ताह में चीनी के दाम तीन फीसदी घट गए हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने जनवरी और फरवरी 2019 में क्रमश: 18.5 लाख टन और 21 लाख टन चीनी के कोटे का आवंटन किया था।

मासिक कोटे में भारी बढ़ोतरी से हाजिर बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ गई है, जिससे इसकी कीमतों में गिरावट आई है। सरकार जून 2018 से मिलों के लिए खुले बाजार में चीनी बिक्री का मासिक कोटा तय कर रही है। मार्च में सबसे अधिक कोटा तय किया गया है, जिससे हाजिर बाजार में चीनी के दाम एक रुपया प्रति किलोग्राम घट गए हैं।

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा, 'मार्च 2019 में बिक्री के लिए सबसे अधिक कोटा तय किए जाने से चीनी के दाम एक रुपया प्रति किलोग्राम कम हो गए हैं। इसका मिलों पर नकारात्मक असर पड़ेगा और हाल में सरकार की तरफ से उठाए गए कुछ कदमों से मिलने वाला फायदा निष्प्रभावी हो जाएगा।'

इसके विपरीत चार चीनी कंपनियों – धामपुर शुगर मिल्स, डालमिया भारत शुगर ऐंड इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी मिल्स और त्रिवेणी इंजीनियरिंग ऐंड इंडस्ट्रीज के शेयर आज बंबई शेयर बाजार में 52 सप्ताह के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए। मुंबई के पास वाशी थोक मंडी में चीनी एम का भाव 32.80 रुपये है, जो दो सप्ताह पहले 33.80 रुपये प्रति किलोग्राम के हालिया ऊंचे स्तर से एक रुपया कम है। हालांकि कीमतों में इस गिरावट की वजह बाजार में चीनी की भरपूर आपूर्ति के कारण कमजोर रुझान हो सकता है।

चीनी उत्पादन

चीनी सीजन (अक्टूबर-सितंबर)	उत्पादन (करोड़ टन)
2012-13	2.51
2013-14	2.44
2014-15	2.83
2015-16	2.51
2016-17	2.03
2017-18	3.25
2018-19*	2.48

*फरवरी 2019 तक, स्रोत : इस्मा, संकलन : बीएस रिसर्च

केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए कई कदम उठाए हैं। पहला, सरकार ने फरवरी में न्यूनतम बिक्री कीमत दो रुपये बढ़ाकर 31 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। इसका मकसद मिलों के पास पूंजी उपलब्धता में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी करना है। इस समय मिलों के पास 170 लाख टन चीनी का स्टॉक है। वहीं आगे 70 लाख टन चीनी का और उत्पादन होने का अनुमान है।

केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का अनुमान है कि एमएसपी में बढ़ोतरी से गन्ने के बकाये में चीनी सीजन 2018-19 में करीब 3,400 करोड़ रुपये की कमी आएगी। उनके इस अनुमान में यह माना गया है कि दो रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी का इस्तेमाल गन्ना बकाया भुगतान में होता।

दूसरा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने चीनी उद्योग के लिए 7,900 से 10,540 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन को मंजूरी दी है ताकि मिलें अपना बकाया चुका सकें और उनके पास पूंजी उपलब्धता में सुधार आए। इस योजना के तहत सरकार एक साल के लिए 553 करोड़ रुपये से 1,054 करोड़ रुपये तक की राशि पर ब्याज में सात से 10 फीसदी छूट का बोझ उठाएगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि यह सॉफ्ट लोन केवल उन मिलों को मिलेगा, जिन्होंने अक्टूबर, 2018 से शुरू हुए चालू सीजन में बकाये का कम से कम 25 फीसदी भुगतान कर दिया है।

इस बीच केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने अनुमान जताया है कि 1 अक्टूबर, 2018 से 22 फरवरी, 2019 के बीच कुल गन्ना बकाया 20,159 करोड़ रुपये है। यह बकाये का रिकॉर्ड स्तर है और ऐसा फरवरी के महीने में कभी नहीं देखने को मिला। मंत्रालय को उम्मीद है कि सॉफ्ट लोन और एमएसपी में बढ़ोतरी से गन्ने के बकाये के जल्द भुगतान में मदद मिलेगी।

एनआईएनएल : स्पेशल ग्रेड स्टील बिलेट का उत्पादन शुरू

बीएस संवाददाता
भुवनेश्वर, 6 मार्च

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) ने इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन टावरों के ढांचों के लिए स्पेशल ग्रेड के इस्पात पाइप (बिलेट) का उत्पादन सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। कलिंगनगर (ओडिशा) स्थित यह इस्पात संयंत्र अपनी आधुनिक स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस) में स्टील बिलेट का निर्माण करता है। यह संयंत्र दिसंबर 2018 में शुरू हुआ है।

इस उपलब्धि के साथ देश की सबसे बड़ी कच्चे लौह की उत्पादक एवं निर्यातक एनआईएनएल ने विद्युत पारेषण एवं वितरण खंड के लिए स्पेशल ग्रेड के स्टील बिलेट की आपूर्ति में बड़ी भागीदारी का लक्ष्य रखा है। विद्युत पारेषण एवं वितरण खंड देश में तेजी से बढ़ रहा है। सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपाय इस ग्रेड के बिलेट तैयार करने के लिए जरूरी हैं। एनआईएनएल अपने स्वयं के टीएमटी ब्रांड के तहत भी कन्वर्जन एजेंट के जरिये इसकी बिक्री करने की योजना बना रही है।

कंपनी ने हाल में बिलेट को टीएमटी रीबार्स में तब्दील करने के लिए आशय पत्र भी जारी किया था। इसका मकसद उन संभावित इस्पात प्रसंस्करण इकाइयों की पहचान करना था जो कन्वर्जन एजेंट के तौर पर एनआईएनएल के बिलेट को टीएमटी रीबार्स में तब्दील करने को इच्छुक होंगी। इच्छुक एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, एनआईएनएल नियोजित कन्वर्जन के लिए उनके साथ अनुबंध करेगी।

लक्ष्य पर नजर

- कंपनी ने विद्युत पारेषण एवं वितरण खंड के लिए स्पेशल ग्रेड के स्टील बिलेट की आपूर्ति में बड़ी भागीदारी का लक्ष्य रखा है
- इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन टावरों के ढांचों के लिए किया जा रहा है इनका उत्पादन
- देश में तेजी से बढ़ रहा है विद्युत पारेषण एवं वितरण खंड

कन्वर्जन एजेंट का कार्य एनआईएनएल के इस्पात संयंत्र परिसर से बिलेट उठाना और इन्हें कन्वर्जन स्थल तक पहुंचाना होगा। एजेंट की जिम्मेदारी बिलेट की अनलोडिंग, हैंडलिंग, स्टैकिंग और भंडारण तथा इन्हें एनआईएनएल की जरूरत के हिसाब से तैयार उत्पादों में तब्दील करने की होगी। इसके बाद तैयार उत्पाद कन्वर्जन एजेंट के कार्य स्थल पर सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।

शुरू में, एनआईएनएल ने हर साल 150,000 टन बिलेट को तब्दील करने की योजना तैयार की है। कन्वर्जन एजेंट एक खास अवधि के लिए यह ठेका दिया जाएगा। यह अवधि दो साल से कम की नहीं होगी और आपसी सहमति से इसे एक साल तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए, कन्वर्जन एजेंट को कम से कम तीन साल के अनुभव और उत्पादन के लिए वैध लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत होगी। एनआईएनएल के कलिंगनगर संयंत्र की सालाना क्षमता 11 लाख टन की है।

नई दिल्ली | 7 मार्च 2019 गुरुवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

'राफेल के दस्तावेज चोरी'

सरकार ने कहा है कि वह उन अखबारों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के बारे में विचार कर रही है, जिन्होंने रक्षा सौदे के ब्योरे प्रकाशित किए हैं

आशिष आर्यन

समाचार-पत्रों ने जिन दस्तावेजों के आधार पर फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में कथित गड़बड़ियों को लेकर ब्योरे प्रकाशित किए हैं, वे रक्षा मंत्रालय से इसी मंत्रालय के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों द्वारा चुराए गए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में यह बात कही।

महान्यायवादी के के वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि ये दस्तावेज रक्षा सौदों से संबंधित हैं और शासकीय गोपनीयता अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसलिए सरकार उन समाचार पत्रों के खिलाफ 'आपराधिक कार्रवाई' के बारे में विचार कर रही है, जिन्होंने ये खबरें प्रकाशित की हैं। सरकार उन याचियों पर भी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने इनका अपनी याचिका में इस्तेमाल किया है।

महान्यायवादी वेणुगोपाल ने कहा कि इन खबरों और याचिकाओं में ऐसे अति गोपनीय रक्षा दस्तावेज शामिल हैं, जिन्हें चुराया गया है। इसलिए शीर्ष अदालत को समीक्षा याचिका खारिज करे। हालांकि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई वाले तीन सदस्यीय पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया। पीठ ने सवाल किया कि अगर ये दस्तावेज चुराए गए हैं, लेकिन उस बिंदु को साबित करते हैं जो याची उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या अदालत को इस पर विचार करना चाहिए या नहीं? पीठ ने यह भी सवाल किया कि जब भ्रष्टाचार का मामला हो तो क्या केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क के पीछे छिप सकती है?

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने महान्यायवादी वेणुगोपाल से पूछा, 'अगर भ्रष्टाचार का सवाल हो तो क्या कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क की आड़ ले सकता है?' अदालत ने सरकार से पूछा कि अगर वास्तव में रक्षा मंत्रालय से लड़ाकू विमान के सौदे से संबंधित चोरी हो गए हैं तो उसने अभी तक क्या कदम उठाए हैं। अदालत के सवाल का जवाब देते हुए महान्यायवादी ने कहा कि चोरी के वास्तविक स्रोत का पता लगाने के लिए एक जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस संबंध में अभी तक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज नहीं कराई गई है।

अदालत में सुनवाई

- केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कही दस्तावेज चोरी की बात
- महान्यायवादी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों ने चुराए दस्तावेज
- सरकार ने अदालत में राफेल मामले से जुड़ी समीक्षा याचिका खारिज करने की मांग की

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई वाला तीन सदस्यीय पीठ उन याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था, जिनमें राफेल लड़ाकू विमान सौदे की खरीद में जांच को खारिज करने वाले अदालत के फैसले की समीक्षा की गुजारिश की गई थी। यह समीक्षा याचिका पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा एवं अरुण शौरी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दायर की है।

शीर्ष अदालत ने 14 दिसंबर को वे सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिनमें फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान सौदे की खरीद की अदालत की निगरानी में जांच का आग्रह किया गया था। उस समय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उसे 'फैसले की प्रक्रिया में संदेह लायक कोई चीज नहीं मिली है' और वह इसलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

उस समय न्यायालय ने कहा था, 'इस अदालत को ऐसी कोई वजह नजर नहीं आ रही है, जिसके आधार पर वह भारत सरकार के 36 रक्षा विमान खरीद के संवेदनशील मुद्दे में हस्तक्षेप करे। लोगों की धारणा वह आधार नहीं हो सकती, जिस पर अदालत ऐसे मामलों में जांच का आदेश दे।' शीर्ष अदालत के समक्ष पेश समीक्षा याचिका में सिन्हा, शौरी और भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार ने लड़ाकू विमान सौदे से संबंधित अहम तथ्य छिपाए हैं और इसलिए अदालत को गुमराह किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब उच्चतम न्यायालय मूल याचिका पर सुनवाई कर रहा था, तब अदालत ने केंद्र की तरफ से सौंपे गए नोट के 'स्पष्ट रूप से गलत' दावों पर भरोसा किया।

भूषण ने सरकार के इस आग्रह का विरोध किया कि इस लड़ाकू विमान सौदे में जांच का आदेश देना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह होगा और इसलिए मामले में न्यायालय दखल न दे। भूषण ने कहा कि यह अचंभित करने वाली बात है। भूषण ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत में कहा, 'यह अचंभित करने वाली बात है कि रक्षा सौदे के मामले में अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो जांच एजेंसी का यह कर्त्तव्य है कि वह इस अदालत की संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक जांच करे। यह अलग चीज है कि अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वे क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करें।' भूषण ने सीएजी की रिपोर्ट पर भी अचंभा जताया, जिसमें राफेल लड़ाकू विमान की कीमत से संबंधित ब्योरों को संपादित किया गया है। यह रिपोर्ट हाल में संसद में पेश की गई थी। भूषण ने कहा, 'सीएजी के रक्षा सौदे की ऑडिट में कीमत से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। सीएजी के इतिहास में पहली बार सरकार के कहने पर कीमत ब्योरों को संपादित किया गया है।' इस मामले की अदालत में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।

धमकियों और गालियों से नहीं परेशान : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और कर्नाटक में जनसभाएं संबोधित करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना

- मोदी ने कहा, विपक्ष देश को आगे ले जाने की योजना स्पष्ट रूप से बताए
- राहुल ने कहा, राफेल दस्तावेजों की चोरी मामले पर पर्दा डालने की कोशिश
- विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर कसा तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह खुद को मिल रही धमकियों और गालियों से परेशान नहीं हैं और वह भारत को मजबूत बनाने के लिए हर जरूरी काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी हत्या किए जाने संबंधी कांग्रेस नेता की एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं धमकियों और गालियों को लेकर परेशान नहीं हूं। भारत को मजबूत करने के लिए जो कुछ जरूरी है, उसे करूंगा।' मोदी ने विपक्ष की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि वे लोग राजनीति और स्वार्थी हितों से दिशानिर्देशित हैं और कभी मजबूत भारत या मजबूत सशस्त्र बल नहीं चाहा।

उन्होंने कहा कि विपक्ष को राष्ट्र को आगे ले जाने की अपनी योजना को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। उन्होंने विपक्ष के खिलाफ अपने महामिलावट तंज को भी दोहराया। मोदी ने यह याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए लगभग 50 (राज्य) सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। उन्होंने एम. के. स्टालिन नीत पार्टी (द्रमुक) पर प्रहार करते हुए कहा, 'मूल्यों से ऊपर अवसरवादिता हो गई है।' अन्नाद्रमुक के साथ भाजपा का चुनावी गठबंधन होने के बाद मोदी ने तमिलनाडु में अपनी प्रथम जनसभा में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर राज्य के दिवंगत मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन के नाम पर करने की घोषणा की। मोदी ने कहा कि राज्य के सत्तारूढ़ दल की काफी समय से लंबित एक मांग पूरी करते हुए हमने चेन्नई सेंट्रल स्टेशन का नाम महान एमजीआर के नाम पर करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को कर्नाटक के लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में एक पूर्ण बहुमत की सरकार चुनने का आग्रह करते हुए इस बात पर बल दिया कि महामिलावट सरकार आधा परिणाम देगी। मोदी ने साथ ही भाजपा विरोधी गठबंधन बनाने के विपक्षी दलों के प्रयासों को स्वार्थ की राजनीति बताते हुए निशाने पर लिया और कहा कि वे केवल मोदी हटाओ एजेंडे से निर्देशित हैं। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ में आयोजित एक जनसभा में मोदी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने पर वायुसेना के हवाई हमले की ओर इशारा करते हुए आज अपने दमखम की बात की। उन्होंने कहा, 'वह मोदी के कारण नहीं बल्कि 125 करोड़ लोगों के (संकल्प) चलते हुआ।' उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में एक निरीह सरकार है। मोदी ने कहा कि गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और जदएस अलग-अलग दिशा में खींच रहे हैं।

प्रधानमंत्री पर मुकदमे के लिए पर्याप्त सबूत: राहुल

राफेल विमान सौदे से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी होने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि इस घोटाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि दस्तवेजों के चोरी होने की बात करना सबूत को नष्ट करना और मामले पर पर्दा डालने की कोशिश है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'राफेल घोटाले में प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए अब पर्याप्त सबूत है। भ्रष्टाचार की शुरुआत उन्हीं से होती है और उन पर ही खत्म होती है।' कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, 'राफेल मामले की अहम फाइलों से वह फंस रहे थे।' अब सरकार ने कहा कि ये फाइलें चोरी हो गई हैं। यह सबूत को नष्ट करना और मामले पर पर्दा डालना है।

कितने मच्छर मारे, ये गिनने बैठूं या सो जाऊं? : सिंह

पाकिस्तान में वायुसेना की कार्रवाई में मारे गए आतंकवादियों की संख्या के संदर्भ में कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप बुधवार को भी जारी रही। कांग्रेस नेताओं के बयान पर तंज कसते हुए विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने पूछा कि रात में हिट से कितने मच्छर मारे, उसे गिनने बैठूं या आराम से सो जाऊं? *भाषा*

सशस्त्र बलों ने मांगा अतिरिक्त साजो-सामान

अभिषेक रक्षित

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने आयुध निर्माण बोर्ड (ओएफबी) से विशेष सामान की अतिरिक्त मांग की है। बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या भारतीय सशस्त्र बलों की किसी इकाई ने रक्षा सामानों की तेज डिलिवरी या अतिरिक्त ऑर्डर की मांग की थी, ओएफबी अध्यक्ष सौरभ कुमार ने कहा, 'भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों इकाइयों के पास रक्षा सामानों की कोई कमी नहीं है और उनको पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। हालांकि हाल के दिनों में कुछ अतिरिक्त मांग की गई है।' वह सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

यह पूछे जाने पर कि अगर थल सेना की ओर से कोई मांग आई, कुमार ने कहा, 'इस बार, यह हवाई कार्रवाई थी।' हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से बताने से मना कर दिया। ओएफबी पश्चिम बंगाल में अपने एक कारखाने में एंटी-एयरक्राफ्ट गन के निर्माण को भी दोबारा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अब भारत तथा विदेश से इन उपकरणों की मांग बढ़ रही है।' ओएफबी आयुध तथा रक्षा उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के लिए दूसरे देशों से भी बातचीत कर रही है।

ओएफबी वर्ष 1962 से एंटी-एयरक्राफ्ट गन का उत्पादन कर रही है और उसने वर्ष 1999 में

अपनी क्षमता को बढ़ाकर 12.7 एमएम एयर डिफेंस गन का भी उत्पादन करने लगी थी। हालांकि इस तरह के उपकरणों की मांग में कमी के चलते उत्पादन काफी मंद पड़ गया।

कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना ने 114 लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन (धनुष) का ऑर्डर दिया है जिसे ओएफबी द्वारा विकसित किया जाता है। कुमार को उम्मीद है कि भारतीय सेना से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद 155 एमएम मॉर्डन आर्टिलरी गन-धनुष की मांग बढ़ेगी। इसके उत्पादन में 81 प्रतिशत स्वदेशी सामान का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में ओएफबी के पास करीब 1,000 करोड़ रुपये कीमत की धनुष आर्टिलरी गन के ऑर्डर हैं।

'सैटेलाइट तस्वीरों में नहीं दिखता नुकसान'

जैश के बालाकोट ठिकाने के भारतीय हवाई हमले में तबाह हो जाने के दावे पर सैटेलाइट तस्वीरों से खड़े हुए सवाल

रॉयटर्स

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण में यह पाया है कि पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का प्रशिक्षण शिविर अब भी उसी तरह दिख रहा है जैसा वह भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के पहले था।

रॉयटर्स ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित निजी सेटेलाइट संचालक फर्म प्लेनेट लैब्स इंक से मिली तस्वीरों का विशेषज्ञों के जरिये विश्लेषण कराने के बाद यह सनसनीखेज दावा किया है। रॉयटर्स ने इस विश्लेषण में पाया है कि जैश के नियंत्रण वाले इस परिसर में हवाई हमले के छह दिन बाद 4 मार्च को भी 6 इमारतें मौजूद हैं।

हालांकि एक अन्य समाचार एजेंसी के अनुसार सरकारी सूत्रों ने नई दिल्ली में बताया कि भारतीय वायु सेना ने सरकार को रडार और उपग्रह तस्वीरें सौंपी हैं। इन तस्वीरों में पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविर के 'लक्षित निशाने' पर बमबारी और उसे भारी नुकसान दिख रहा है।

यह दावा भारतीय वायुसेना के हमले में जैश का यह ठिकाना ध्वस्त होने पर सवाल खड़े करता है। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को तड़के बालाकोट के पहाड़ी इलाके में मौजूद इस शिविर पर बम बरसाए थे। इस हमले में आतंकवादियों के बड़ी संख्या में मारे जाने की बात कही गई थी। अर्द्धसैनिक बल सीआरपीएफ के काफिले पर पुलवामा में हुए आत्मघाती धमाके की जिम्मेदारी जैश ने ली थी। उसके बाद ही बालाकोट में मौजूद जैश के इस प्रशिक्षण शिविर को वायुसेना ने निशाना बनाया था।उस हमले में आतंकियों को प्रशिक्षण देने वाले इस शिविर को हुए नुकसान और मारे गए आतंकवादियों की संख्या को लेकर असमंजस बना हुआ है। जहां सरकार ने मारे गए लोगों की सटीक संख्या को लेकर कोई दावा नहीं किया है वहीं इस पर राजनीतिक दलों में खींचतान मची हुई है। हालांकि अभी तक उस शिविर के बारे में उच्च गुणवत्ता वाली सेटेलाइट तस्वीर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होने से इन दावों की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। लेकिन प्लेनेट लैब्स से मिली तस्वीरें 72 सेंटीमीटर तक की बारीक जानकारी को भी कैद किए हुए हैं। इतने करीब से खिंची गई तस्वीरों से पता चलता है कि 4 मार्च को उस जगह पर अब भी 6 इमारतें मौजूद हैं।अगर इस परिसर की अप्रैल 2018 को ली गई एक अन्य तस्वीर से तुलना करें तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं दिखता है। इमारतों पर बम गिरने से होने वाले नुकसान की कोई भी निशानी नहीं नजर आ रही है। न तो दीवारों पर जलने के निशान हैं और न ही हमले से बने गड्ढे नजर आते हैं। यहां तक कि आसपास के पेड़ भी सही-सलामत नजर आ रहे हैं। सेटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण में महारत रखने वाले जेफ्री लेविस ने 4 मार्च को ली गई तस्वीरों में 6 इमारतें मौजूद होने की पुष्टि की है। मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनैशनल स्टडीज में पूर्व-एशिया अप्रसार परियोजना के निदेशक जेफ्री ने कहा, 'उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों में बम से हुए नुकसान का कोई साक्ष्य नहीं दिख रहा है।' उन्होंने कुछ घंटों के ही भीतर ली गई तीन अन्य तस्वीरों को भी देखने के बाद यह निष्कर्ष रखा है। अगर प्लेनेट लैब्स की इन तस्वीरों पर यकीन करते हैं तो हवाई हमले में शिविर को तबाह कर देने का दावा संदेह के घेरे में आ जाता है।

- रॉयटर्स के मुताबिक हमले के छह दिन बाद भी जैश के ठिकाने की 6 इमारतें मौजूद थीं

भारतीय वायु सेना ने सरकार को रडार और उपग्रह से मिली तस्वीरें सौंपी